साप्ताहिक
शांति मिशन
नई दिल्ली

वर्ष-29 अंक- 02 09 - 15 जनवरी 2022 पृष्ठ 12

अन्दर पढ़िए

अवसाद में घिरता बचपन
पृष्ठ - 6

जातिगत समीकरणों के विरुद्ध संघ की शपथ का भाजपा पर कितना असर
पृष्ठ - 7

संविधान और क़ानून की बेअदबी करने वालों का राजनीति महिमामंडन किया जा रहा है

इस गुस्ताख़ी को बहुमत की बेअदबी ही कहा जाएगा

भीड़ की हिंसा-पिछले कुछ सालों में यह भयावह शब्द भारत के राजनीतिक शब्दकोष में शामिल हो चुका है। भीड़ हिंसा का भय क़ायम हो गया है। इस तरह की घटनाएं आख़िर क्यों बढ़ रही हैं?

बीते वर्ष लोकतंत्र शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी अहम रही थी। दुनिया के नक्शे पर सफल लोकतंत्र की बात आते ही भारत सहचर शब्द के रूप में उभरता है। दिल्ली की सीमा पर स्थगित हुए किसान आंदोलन को हमने अपने लोकतंत्र की बड़ी सफलता के रूप में देखा था। लेकिन उसके बाद पंजाब से लेकर उत्तराखंड में हुआ वह हमारे लिए ख़तरे की घंटी ही कही जाएगी। जिस राज्य की ज़मीन पर किसान आंदोलन शुरू हुआ उसी पंजाब में दो लोगों को पीट-पीटकर हत्या होती है। हरिद्वार में धर्म संसद के नाम पर एक विशेष समुदाय के ख़िलाफ़ पूरी तरह हथियार उठाने का नफ़रत भरा आहवान किया गया। इस तरह के ज़्यादातर मामलों में व्यवस्था अपना काम कर रही है, का दिलासा देकर सरेआम क़ानून व संविधान की बेअदबी पर हर कोई ख़ामोश हो जाना चाहता है। धार्मिक बेअदबी की निंदा कर उस हत्या पर बोलने से परहेज़ किया जाने लगा है जिसे हमारे राजनीतिक शब्दकोष में भीड़ के द्वारा की गई हत्या का नाम दिया जा चुका है। एक ऐसा शब्द जो लगातार हमारे लोकतंत्र को सलीब पर लटका रहा है।

दिल्ली के जंतर-मंतर मेरे नाम पर नहीं (नाट इन माय नेम) के मंच से भाषण देने वाले नेता अन्य जगहों पर पुख़्ता जानकारी की प्रतीक्षा और साज़िश शब्द से ही काम चला रहे थे। क़ानून ने तो अपना काम किया लेकिन आप इस माहौल के ख़िलाफ़ बोलने में इतनी देर क्यों कर रहे थे। चौराहे पर फांसी देने वाली बात तो नेता बोल देते हैं जिन्होंने संविधान की शपथ लेकर, उसकी रक्षा का वचन देकर संसद में प्रवेश किया है।

जिस राज्य ने आज़ादी के बाद हुए एक सफल ऐतिहासिक आंदोलन का जश्न मनाया वहां भी इस तरह की हत्या होना दुर्भाग्यपूर्ण है। चाहे भाजपा के नेता हों या दिल्ली सीमा पर जुझारूपन दिखा चुके किसान नेता या पंजाब में नई तरह की राजनीति करने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी। इनके लिए पंजाब अभी सिर्फ विधानसभा चुनाव की ज़मीन है जहां ये बहुमत के ख़िलाफ बोलकर अपने लिए किसी तरह के कांटे नहीं बोना चाहते।

दादरी से लेकर अमृतसर, कपूरथला व हरिद्वार तक को समझने के लिए हमें धर्म और सत्ता के इतिहास को एक बार खंगाल ही लेना चाहिए। मध्यकाल का पूरा इतिहास बताता है कि धर्मसत्ता और राजसत्ता में गहरा संबंध है। दोनों एक-दूसरे से विस्तार पाते हैं। भारत में भी प्राचीनकाल से ही धर्मसत्ता के ज़रिए ही राज्यसत्ता ने अपना विस्तार पाया। यूरोप में पुनर्जागरण के बाद विज्ञानवाद का समय आया। वहां तक आते-आते एक चीज़ समझ आई कि धर्म व्यक्ति की निजी मुक्ति का मामला है। उसके बाद से धर्म को उदार नज़रिए से देखा जाने लगा।

प्राचीन, मध्य और आधुनिक का फर्क व्यक्ति-सत्ता और धर्म के बीच के संबंधों का फर्क भी है। दुनियाभर में आधुनिकता की अवधारणा उदार सत्ता और उदार धर्म के साथ ही स्थापित होती है। दुनिया में वही देश सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से विकसित हुए जिन्होंने अपने क़ानून और विधान से धार्मिक कट्टरता को दूर रखा है।

भारत में कबीर और गुरु नानक जैसे संतों ने धर्मसत्ता के सताए लोगों को नया आध्यात्मिक आधार दिया। गुरुओं के शुरू किए उदार पंथ ने उन लोगों की आध्यात्मिक भूख शांत करने की भूमिका निभाई। धर्मसत्ता और राजसत्ता के ज़रिए हाशिए पर भेजे गए लोगों में आत्मविश्वास पैदा किया कि वो अपने आत्म को परमात्म से जोड़ सकें। भारत के जागरण काल में भी चाहे विवेकानंद हों या स्वामी रामकृष्ण परमहंस वाली परंपरा, उनसे जुड़े लोगों ने लगातार धर्म की आध्यात्मिक भूमिका पर ज़ोर दिया। धर्म जितना उदार होगा व्यक्ति उसके साथ उतना ही सहज, सरल और स्वतंत्र होगा और किसी के व्यक्तित्व को उदार विस्तार देगा।

धर्म को राजसत्ता से अलग करने की मुहिम के साथ ही जनतांत्रिक मूल्य भी पैदा हुआ। इसी जनतांत्रिक मूल्य के आधार पर पूरे संविधान की रचना हुई। वह संविधान जो व्यक्ति को केन्द्र में रख कर उसकी स्वतंत्रता को तय करने का लक्ष्य रखता है। यह जनतांत्रिक लक्ष्य उसी राह से अर्जित है जो एक समय में उदार धार्मिक पंथों ने दिखाई थी। धर्मसत्ता या राजसत्ता के नियम से अलग हटकर व्यक्ति की सत्ता को केन्द्र में रखकर व्यक्ति की मुक्ति का आध्यात्मिक आधार देखा। इसी मूल्य ने आज के संवैधानिक नागरिक की बुनियाद रखी। नागरिक शब्द का भावार्थ है व्यक्तिगत स्वतंत्रता और नैतिक कर्तव्यबोध का भान।

संविधान स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा को मानता है। यह जनतांत्रिक मूल्यों से संचालित होता है न कि बहुमत की संख्या को किसी भी फैसले का आधार बनाता है। जो बहुमत को पसंद हो ज़रूरी नहीं कि वो संवैधानिक और जनतांत्रिक भी हो। हमारे संविधान के जनतंत्र का आध्यात्मिक आधार भी है। महात्मा गांधी भी उपनिवेशवाद के ख़िलाफ़ लड़ाई में इसी मूल्य को लेकर आगे चले थे। उनकी राजनीतिक मुहिम में नगर ईश्वर, अल्लाह, तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान का नारा शामिल था तो इसलिए कि सारे भेदभाव भुलाकर हम व्यक्ति के तौर पर अपनी स्वतंत्रता के लिए सेनानी बन सकें।

हमारी इस आध्यात्मिक जनतांत्रिक परंपरा को तोड़ कर उसे बहुमतवाद में बदलने की कोशिश हो रही है। पहले बहुमत का धर्म अपनाओ और फिर उस धर्म के मंच का सहारा लेकर देश के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की हत्या का आहवान करो। हरिद्वार में हुई कथित धर्म संसद उस संसद के लिए ख़तरा है जनता के द्वारा चुनी जाती है। आज चुनावों के समय कोई अयोध्या की यात्रा करवा रहा है तो कोई काशी का गलियारा बनवा रहा है। कथित सेकुलर दल के नेता धार्मिक बेअदबी पर कानून बना देने की बात कर रहे हैं। जो भी राज्य चुनाव के मुहाने पर होता है वहां सभी दल खुद को धर्म कांटे पर तुलवाने लगते हैं।

भारत सामाजिक व सांस्कृतिक रूप से एक धार्मिक देश है। यहां चुनावों के समय पर धर्म को लेकर जो विशेष तरह का शोर मचाया जाने लगा है और खास तरह की चुप्पी साधी जाने लगी है उस पर सबसे पहले नागरिकों को ही चेतना होगा। कहीं पर भी भीड़ की हिंसा पर चुप्पी साधी जाएगी तो अन्य जमीनी मुद्दों पर भी चुप्पी साधने

बाक़ी पेज 11 पर

हमारी इस आध्यात्मिक जनतांत्रिक परंपरा को तोड़ कर उसे बहुमतवाद में बदलने की कोशिश हो रही है। पहले बहुमत का धर्म अपनाओ और फिर उस धर्म के मंच का सहारा लेकर देश के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की हत्या का आहवान करो। हरिद्वार में हुई कथित धर्म संसद उस संसद के लिए ख़तरा है जनता के द्वारा चुनी जाती है। आज चुनावों के समय कोई अयोध्या की यात्रा करवा रहा है तो कोई काशी का गलियारा बनवा रहा है। कथित सेकुलर दल के नेता धार्मिक बेअदबी पर कानून बना देने की बात कर रहे हैं। जो भी राज्य चुनाव के मुहाने पर होता है वहां सभी दल खुद को धर्म कांटे पर तुलवाने लगते हैं।

कभी अंतर्राष्ट्रीय मदद के भरोसे रहने वाला 'बांग्लादेश' आज मध्यम आय वर्ग वाले देशों में शामिल

50 सालों में बांग्लादेश ने जादू ही तो किया है

बांग्लादेश को आज़ाद हुए 50 वर्ष का समय हो गया है। जो देश कभी अंतर्राष्ट्रीय मदद के भरोसे रहता था, वह इतने कम समय में मध्य आय वाला देश बन जाएगा, ऐसा हम में से शायद किसी को अनुमान न होगा। एक दशक से भी ज़्यादा वक्त से बांग्देश की जीडीपी ग्रोथ 6 प्रतिशत बनी हुई है। शिशु जन्म दर 07 से नाटकीय ढंग से गिरकर 2.03 पर आ गई है। नवजात और शिशु मृत्यु दर में भी भारी गिरावट आई है। शिक्षा के मामले में लड़के लड़कियों में फसला नहीं रह गया है। आपदा प्रबंधन में भी हम वैश्विक ताक़त बन गए है। और हां, हमने अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप भी जीता है। वह भी अपने बड़े पड़ोसी को हराकर। 50 सालों में विकास को लेकर हमने एक जादू किया है। इस जादू के लिए जो रास्ता चुना गया, वह अनोखा है, बिल्कुल बांग्लादेशी। आख़िर हम ये मुक़ाम हासिल कैसे कर पाए.?

इतिहास, मौक़ा और सरकार की होशियारी। ये बांग्लादेश की सफलता की बुनियाद है। 70 के दशक की शुरुआत में युद्ध और तबाही मचाने वाले तूफान से रिकवरी के साथ हमारा इतिहास शुरू हुआ। इसके लिए सामुदायिक स्तर पर पहल हुई, जिसमें ग़ैर सरकारी तंत्र ने बड़ी भूमिका निभाई। इस पहल में ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों ने तक़दीर संवारने का ज़िम्मा अपने हाथों में लिया। इसी पहल ने आगे चलकर बांग्लादेश में ताक़तवर एनजीओ आंदोलन का रूप ले लिया। इस रिकवरी के असल नायक विदेश में काम करने वाले वर्कर्स थे। जो अपनी कमाई गांवों में रहने वाले अपने परिवार के पास भेजते रहे। इस रिकवरी के लिए हमें तकदीर की मदद और अवसरों की दरकार भी थी। तेल उत्पादक देशों (ओपेक) की अर्थव्यवस्था में तेजी आई, उससे वहां बड़े पैमाने पर लोगों को रोज़गार मिला। उन वर्कस को भेजा गया पैसा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में लगा, उनके घर की औरतों के ज़रिये। इन औरतों के ख़र्च करने का तरीका भी अलग था। उन्होंने इसका इस्तेमाल बच्चों को शिक्षित और हुनरमंद बनाने के लिए किया। इससे महिला सशक्तीकरण की भी शुरुआत हुई, जो बांग्लादेश के विकास की एक और अनोखी कहानी है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इस तरह से जो पैसा लगा, वह सरकारी योजनाओं से अधिक फायदेमंद साबित हुआ। ग़ैर सरकारी संस्थानों की पहल और इस निवेश ने सामुदायिक पहल को बढ़ावा दिया। लोगों में पहले से उद्यमशीलता थी। ये लोग दूसरी जगहों से आकर इस उपजाऊ क्षेत्र में बसे और लगातार आने वाली आपदाओं से जूझना और उबरना सीखा। तब तक वजूद बनाए रखने के लिए उन्होंने जो तरीके आज़माए, वही उसके बाद राष्ट्र निर्माण के काम आए। इतिहास ने हमारे सामने जो अवसर पेश किए, उसे लेकर सरकारों का रवैया भी सही रहा। दुनिया में बहुत कम ऐसे देश होंगे, जिन्होंने कर्ज़, स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था का समर्थन किया होगा, जैसा बांग्लादेश में हुआ। सरकार ने 70 के दशक में आख़िर में प्रवासियों की ओर से भेजे जाने वाले पैसों को देखते हुए फॉरेन एक्सचेंज रेट रिफार्म (विदेशी मुद्रा विनियम सुधार) किए। इस तरह से उसने इसे लेकर ब्लैक मार्केट पर रोक लगाई।

गांवों में प्रवासियों की ओर से भेजी जानी वाली रक़म, सामुदायिक स्तर पर सेवाएं देने के तंत्र के उभार और सशक्त एक्सचेंज रेट रिफार्म ने शुरुआती दौर में देश के विकास में बड़ी भूमिका निभाई। फिर सरकार ने कृषि क्षेत्र में सुधार किए। इससे किसानों को बाजार की ताक़तों का फायदा उठाने का मौक़ा मिला। युद्ध के बाद देश के कोने-कोने को सड़क और पुल बनाकर जोड़ा गया। मुझे याद है कि 70 के दशक की शुरुआत में ढाका से हमारे गांव पहुंचने में 9 घंटे लगते थे। आज वह सफर तीन घंटे से भी कम में पूरा हो जाता है। मौक़े बनते रहे और सरकारें उसका फायदा उठाती रहीं। 80 के दशक में एक कोरियाई कंपनी बांग्लादेश में दाख़िल हुई। किस्मत की ही बात है कि इस कंपनी ने बांग्लादेश को वैश्विक बाज़ार के लिए गारमेंट बनाना सिखाया। बांग्लादेश की एक कंपनी ने जो पहल की थी, सरकार की सहायता से उसे व्यापक फल मिला। सरकार की पहल से सभी गारमेंट एक्सपोर्टर्स को बिना किसी टैक्स के आयतित कच्चा माल मिलने लगा। यह काम बॉन्डेड वेयरहाउस सिस्टम के ज़रिये किया गया।

बांग्लादेश ने शुरू में निर्यात के

बाक़ी पेज 11 पर

होम आइसोलेशन में इलाज का सिस्टम होगा और मज़बूत

दिल्ली में ओमिक्रॉन और कोविड के केसों ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी संक्रमित हो गए हैं। इससे पहले केजरीवाल ने सभी विभागों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की थी। उन्होंने बैठक के बाद यह कहा कि ओमिक्रॉन से निपटने के लिए अस्पतालों में बेड्स, दवाईयों और ऑक्सीजन का पुख़्ता इंतज़ाम है और साथ ही होम आइसोलेशन के सिस्टम पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ज़रूरत पड़ने पर तीन लाख टेस्ट भी हर रोज़ किए जाने की व्यवस्था है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार हर रोज़ एक लाख केस को आधार मानकर अपनी तैयारियों को अंजाम दे रही है। दिल्ली में हुए सीरो सर्वे में 95 प्रतिशत लोगों में एंटीबॉडी मिली है और 70 प्रतिशत लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। ऐसे में संभव है कि ओमिक्रॉन का प्रकोप ज़्यादा भयावह रूप न ले पाए, हमने इसके फैलने पर निपटने के लिए पर्याप्त तैयारी कर ली है और अथवा एडवांस तैयारियों में लगे हुए हैं, क्योंकि ओमिक्रॉन बहुत तेज़ी से फैलता है, लेकिन अभी तक इसके लक्षण काफी हल्के हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर ओमिक्रॉन तेजी से फैलता है कि तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर काफी मजबूत होना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो दिल्ली में तीन लाख टैस्ट प्रतिदिन हो सकेंगे। अभी दिल्ली में 60 से 70 हजार टेस्ट हर रोज़ किए जा रहे हैं। बीते वर्ष अप्रैल में कोरोना की लहर में एक दिन में अधिकतम 26 से 27 हजार केस आए थे। इस बार एक लाख केस प्रतिदिन को आधार मानकर तैयारी की जा रही हैं ओमिक्रॉन में हल्का लक्षण है। जनता से अपील है कि आप अपने घर पर रहिए। अगर लक्षण हल्के ही रहते हैं तो फिर घर पर होम आइसोलेशन में इलाज हो सकता है। टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव होने पर दिल्ली सरकार की टीम मरीज़ से संपर्क करेगी और उन्हें एक किट देकर आएगी, जिसमें दवाईयां, ज़रूरत दिशा निर्देश और ऑक्सीमीटर होगा। इसके बाद डॉक्टर फोन पर 10 दिनों तक या उनके ठीक होने तक हर रोज़ टेली काउंसलिंग करेंगे। हम होम आइसोलेशन के लिए जो भी ऐंसी हायर करने की ज़रूरत है, करेंगे। सीएम ने कहा कि मरीज़ों के घर जाने वाली सरकारी टीमों की कैपिसिटी को भी बढ़ाया जा रहा है। अभी करीब एक हजार घरों तक टीमें पहुंच सकती है,ल`किन इसको एक लाख कैसेज की क्षमता को लेकर तैयारी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली बार ऑक्सीजन की कमी हुई थी, लेकिन अब ऑक्सीजन का भी पूरा इंतज़ाम किया गया है। ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रक का इंतज़ाम किया गया है। करीब 27 हजार कोविड बेड्स और 10595 कोविड आईसीयू बेड्स तैयार कर लिया गया है। ❑❑

पहले से रेडी हो चुके हैं कोविड केयर सेंटर : प्रशासन

दिल्ली में कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट अब तेज़ रफ्तार पकड़ रहा है। इसे देखते हुए सरकार और प्रशासन हाई अलर्ट पर है और अभी से आपातकालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ज़रूरी इंतज़ाम किए जा चुके हैं ताकि कोविड की दूसरी लहर के समय जैसा भयावह दृश्य देखा गया उसकी पुनरावृत्ति न हो पाए। कोविड की दूसरी लहर के दौरान मरीज़ों के इलाज के लिए जो अस्थायी कोविड केयर सेंटर और अस्पताल बनाए थे, उन्हें फिर से रेडी किया जा रहा है। सभी जिलों के डीएम अपने-अपने क्षेत्र में बने इस तरह के अस्थायी कोविड केयर सेंटरों का दौरा करके वहां सभी ज़रूरी इंतज़ाम करवा रहे है। कुछ जगहों पर तो मरीज़ों को भर्ती करने के लिए ज़रूरी व्यवस्थाएं की जा चुकी हैं।

कोविड की दूसरी लहर के दौरान छतरपुर स्थित राधास्वामी संत्सग व्यास में बनाए गए 5 हजार बेड की क्षमता वाले सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर को एक बार फिर से मरीज़ों के इलाज के लिए तैयार किया जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक, यहां 150 बेडस तैयार किए जा चुके हैं और ज़रूरत के अनुसार बेड्स बढ़ाने के लिए आगे का पूरा प्लान तैयार किया जा चुका है। सीआईएसएफ को भी तैयार रहने के लिए कह दिया गया है, जिनकी मदद से इस सेंटर का निर्माण और संचालन किया गया था। उधर डीआरडीओ के सहयोग से दिल्ली कैंट में आर्मी के द्वारा बनाए और संचालित किए गए सरदार पटेल कोविड केयर हॉस्पिटल को भी स्टैंड बाय पर रखा गया है। चूंकि इस अस्पताल में कोरोना के गंभीर लक्षणों वाले मरीज़ों का इलाज किया गया था और अभी तक उस तरह की गंभीर स्थिति बनती नहीं दिख रही अगर स्थिति भयावह होती है तो इस अस्पताल को आगे ज़रूरत के अनुसार इस्तेमाल किया जाएगा। कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज में बनाए गए 500 बेड के कोविड केयर सेंटर में भी 50 बेड्स तैयार किए गए हैं, जहां मरीज़ों को तुरंत इलाज या आइसोलेशन के लिए भेजा जा सकता है। अधिकारियों का कहना है कि ज़रूरत पड़ने पर यहां दो दिन के अंदर बेड्स की क्षमता बढ़ाकर 500 तक की जा सकती है। अच्छी बात यह है कि इन सभी जगहों पर ऑक्सीजन प्लांट भी लगाए जा चुके हैं।

संपादकीय

शांति मिशन

सियासत में ज़बान के गिरते स्तर का ज़िम्मेदार कौन?

था कोई ज़माना जब देश में पांच वर्ष में एक बार चुनाव होते थे, पर अब तो चुनाव जैसे एक निरंतर चलती रहने वाली प्रक्रिया बन गए हैं। पहले पांच वर्ष में एक बार नेताओं के चुनावी भाषण देते रहते हैं। चुनावी भाषण का मतलब बन गया है लच्छेदार भाषा, तर्कहीन हमले, लोक लुभावन वादे और झूठे दावे। एक बात और थी हुई है इस दौरान, नेताओं की भाषा में ऐसे शब्द लगातार बढ़ते जा रहे हैं जिन्हें कल तक अशोभनीय समझा जाता था। हाल ही में एक नेता ने ऐसे ही एक शब्द का इस्तेमाल करने का बचाव करते हुए तो यहां तक कह दिया कि, मुझसे ज़्यादा अपशब्द तो भाजपा नेता बोलते हैं। असल में भाजपा की एक महिला नेता ने उनके ख़िलाफ़ पुलिस में शिकायत कर दी है। अब नेताजी यह कहकर अपना बचाव कर रहे हैं कि उस कथित अपशब्द का मतलब हिन्दी में बेवकूफ होता है। प्रश्न उठता है नेताओं को यदि किसी को बेवकूफ ही कहना था तो यही शब्द काम में क्यों नहीं ले लिया? इस सीधे से प्रश्न का उत्तर यह है कि हमारे राजनेता भाषा की मयार्दा के पालन की आवश्यकता नहीं समझते अथवा समझना नहीं चाहते। अप्रिय शब्दों का इस्तेमाल करने की तो जैसे हमारे नेताओं में होड़ लगी रहती है। यही नहीं, कई बार तो ये नेता अच्छे भले शब्दों के अर्थ बिगाड़ देते हैं। ऐसा ही एक शब्द 'अब्बाजान' (पिताजी) है।

उर्दू में पिता के लिए यह शब्द (पिताजी) आदर सहित लिया जाता है। पर हमारे एक नेता ने एक पूरे समुदाय को नीचा दिखाने के लिए इस शब्द को ही नीचा बनाने पर तुले हैं। इन नेता जी की दृष्टि में इस शब्द का कसूर यह है कि यह उर्दू का शब्द है और उर्दू को एक समुदाय विशेष की भाषा मान लिया गया है। उर्दू को एक समुदाय विशेष की भाषा मानना भी ग़लत है और उर्दू के एक आदरसूचक शब्द को अपने चुनावी लाभ के लिए हिकारत के अर्थ में काम में लेना भी। सच पूछा जाए तो भाषा का इस तरह का इस्तेमाल अभद्रता का ही परिचायक है। सभ्य समाज के तौर तरीक़ों का तक़ाज़ा है कि अभद्रता से बचा जाए।

हमारे नेताओं का यह आचरण राजनीति को ही घटिया नहीं बनाता, राजनेताओं के क़द को बौना भी बनाता है। इसी बौनेपन का एक और उदाहरण कपड़ों और रंगों से लोगों या जमातों की पहचान करना भी है। यह सही है कि कपड़े समाज विशेष की पहचान भी हुआ करते हैं, पर जब कोई बड़ा नेता यह कहता है कि ऐसे लोग कपड़ों से ही पहचाने जा सकते हैं तो वह कुल मिलाकर उन लोगों को हेय दृष्टि से देखने का संकेत ही देता है। जैसे चोटी और जनेऊ हिन्दुओं की एक पहचान है, वैसे ही एक विशेष तरह की टोपी मुसलमानों की भी पहचान मानी जाती है। उस टोपी का मज़ाक़ उड़ाने का मतलब समुदाय विशेष पर निशाना साधना है – और इस तरह की निशानेबाज़ी घटिया राजनीति का ही उदाहरण है। भारतीय समाज और परंपरा में टोपी या पगड़ी इज़्ज़त का प्रतीक हुआ करती है।

मज़ाक़ की नहीं, गरिमा की चीज़ होती है – टोपी या पगड़ी। इन्हें किसी के मज़ाक़ का माध्यम बनाना घटिया राजनीति ही कही जाएगी। पिछले दिनों समाजवादी पार्टी की ''लाल टोपी'' के संदर्भ में नेताजी ने सही कहा कि 'लाल टोपी खतरे का प्रतीक माना जाता है, पर लच्छेदार भाषा बोलने के चक्कर में वे यह भूल गए कि लाल रंग शौर्य का भी प्रतीक होता है और जिन्हें वे देश के लिए ख़तरा बताना चाह रहे हैं वे इस लाल रंग को अपने शौर्य से भी जोड़ सकते हैं। जोड़ा भी उन्होंने। जितनी तालियां लाल टोपी को ख़तरे का प्रतीक बताने वाले को मिली थीं, उससे कहीं ज़्यादा तालियां शौर्य का प्रतीक बताने वाले को मिलीं।

पर प्रश्न कम या ज़्यादा का नहीं है, प्रश्न है राजनीति के स्तर के लगातार गिरते जाने के परिणाम का! दुर्भाग्य से, पिछले एक अर्से में इस फिसलन की गति कुछ ज़्यादा ही तेज़ हुई है। प्रतिपक्षी के तर्कों को ख़ारिज करना, उसे नीचा दिखाना हमारी राजनीतिक व्यवस्था का एक हिस्सा है। आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक बहस का साधन है। प्रतिपक्षी की कमज़ोरियों पर वार करना भी क़तई ग़लत नहीं है। पर जनतांत्रिक मूल्यों का तक़ाज़ा है कि मर्यादाहीनता से बचा जाए। पर हमारे राजनेताओं को मर्यादा का ध्यान रखने की शायद ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। राष्ट्रहित का तक़ाज़ा है कि हमारे नेता अपने स्वार्थों से ऊपर उठकर सोचने की आवश्यकता को महसूस करें उनका आचरण मर्यादाओं के पालन का उदाहरण होना चाहिए।

यह किस क़दर अफसोस की बात है कि संसद में हंगामों और अपशब्द बोलने की वजह से जिसमें सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों की सदस्य शामिल रहे हैं लोकसभा और राज्यसभा अधिवेशन एक दिन पहले ही समाप्त कर देना पड़ा है, लोकसभा का यह शीतकालीन सत्र 29 नवंबर को आरंभ हुआ था और उसे 28 दिनों तक चलना था। मगर उसे 27 दिन में ही अचानक अनिश्चित काल के लिए रोक दिया गया इसी शीतकालीन अधिवेशन में राज्यसभा में पूरे 50 घंटे हंगामे और स्थगन की भेंट हो गए। जबकि लोकसभा का भी 19 घंटे की कीमत समय बर्बाद हो गया जो बिला शुब्हा देश की जनता के लिए एक त्रासदी ही है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार की ज़िद और बहुमत के घमंड की वजह से ऐसा हुआ है, जबकि सरकार इसके लिए विपक्षी दलों पर आरोप लगाती रही है, ज़िम्मेदार कोई भी हो बहरहाल संसद चलाने की ज़िम्मेदारी सरकार की होती है इसलिए उसे बहरहाल कोई ऐसा रास्ता निकालना होना जो जनता की मेहनत की कमाई की रक्षा कर सके।

दुर्भाग्य से, मर्यादाहीनता हमारी राजनीति की पहचान बनती जा रही है। कब हमारा नेतृत्व लच्छेदार भाषा के लोभ से मुक्त होगा? कब उसे और ओच्छे विचार राष्ट्र की पहचान को भी ओछा बनाते हैं? नेता यदि यह नहीं समझा पा रहे तो मतदाताओं को उन्हें समझाना होगा।❑❑

तारीख़े इस्लाम

ख़ुतबाते सीरते तैयिबा

मुफ़्ती मुहम्मद सलमान मंसूरपुरी क़िस्त-105

मरज़ुल वफ़ात

सफ़र की 29 तारीख़ को पैग़म्बर अ़लैहिस्सलाम एक जनाज़े में जन्नतुल बक़ी तशरीफ़ ले गए थे, वहीं से वापस आकर आप को बुख़ार का असर ज़ाहिर हुआ, और यह बुख़ार वक़्ते वक़्ते से बढ़ता चला गया, पैग़म्बर अ़लैहिस्सलाम बराबर नमाज़ पढ़ाते रहे लेकिन ज़ोफ़(कमज़ोरी) बहुत ज़्यादा था, ताआँकि 8 या 9 रबीउ़ल अव्वल को आप ने एक मुख़्तसर सा ख़ुतबा दिया, जिस में मुख़्तलिफ़ बातों की जानिब इशारा फ़रमाया, नमाज़ की पाबंदी करना, औरतों के हुक़ूक़ का लिहाज़ रखना, गफ़लाम बाँदियों के हुक़ूक़ का लिहाज़ रखना, और एक ख़ास बात यह फ़रमाई कि : ''देखो! अल्लाह तआ़ला यहूदियों पर लानत करे, उन्होंने अपने अंबिया अ़लैहिमुस्सलाम और बुज़ुर्गों की क़ब्रों पर मस्जिदें बना दीं और क़ब्रों को सज्दा करने लगे, मेरी क़ब्र को सजदागाह मत बनाना, मैं तुम्हें इस से ख़ास तौर पर मना कर रहा हूँ''। (बुख़ारी शरीफ़ 2/639)

आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने ये सब हिदायात उम्मत को दीं ताआँकि वफ़ात से 4 रोज़ पहले जुमेरात के दिन आख़िरी नमाज़ मग़्रिब की अदा फ़रमाई, और उस में सूरह मुरसलात की आयतें पढ़ीं। (बुख़ारी शरीफ़ जि. 2 स. 637)

फिर आप के बुख़ार की शिद्दत इतनी हुई कि इशा की नमाज़ के लिए तैयारी होती थी, टब में पानी लाया जाता और आप वुज़ू फ़रमाते और चेहरे पर छिड़कते लेकिन फिर ग़शी की सी कैफ़ियत हो जाती थी, तीन चार मर्तबा ऐसे ही हुआ, सभी सहाबा मस्जिद में नमाज़ के मुनतज़िर थे।

पैग़म्बर अ़लैहिस्सलाम हज़रत आइशा सिद्दीक़ा रज़ि अल्लाहु अ़न्हा के हुजरे में तशरीफ़ फ़रमा थे, और आप की ख़्वाहिश भी यही थी कि मरज़ का ज़माना यहाँ गुज़रे, आप ने हज़रत आइशा रज़ि अल्लाहु अ़न्हा से फ़रमाया कि:

''अबू बक्र सिद्दीक़ से कहो कि नमाज़ पढ़ायें।

हज़रत आइशा सिद्दीक़ा रज़ि अल्लाहु अ़न्हा फ़रमाती हैं कि मुझे यह बात अच्छी नहीं लगी कि मेरे वालिद हुज़ूर की ज़िंदगी में हुज़ूर की जगह पर खड़े हों, और लोग भी इसको अच्छा नहीं समझेंगे, तो मैंने कहा कि वह कमज़ोर दिल के आदमी हैं, आप की जगह खड़े नहीं हो पायेंगे, इस लिए आप हज़रत उमर को कह दीजिये, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फिर भी फ़रमाया कि नहीं अबू बक्र से कहो। उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ़्सा रज़ि अल्लाहु अन्हा भी वहीं मौजूद थीं, तो हज़रत आइशा सिद्दीक़ा रज़ि अल्लाहु अ़न्हा ने उनको तैयार किया कि तुम सिफ़ारिश करो कि अबू बक्र नहीं उमर नमाज़ पढ़ायें, लेकिन पैग़म्बर अ़लैहिस्सलाम ने सख़्ती से मना फ़रमाया कि तुम ग़लत मशवरा दे रही हो, अबू बक्र से कहो वह नमाज़ पढ़ायें।

यह इस बात की जानिब इशारा था कि पैग़म्बर अ़लैहिस्सलाम के बाद ख़िलाफ़त के मुस्तहिक़ सैयदना हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ि अल्लाहु अ़न्हु ही हैं, क्योंकि पैग़म्बर अ़लैहिस्सलाम ने उनको अपनी जगह इमाम बना दिया, चुनान्चे हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ि अल्लाहु अ़न्हु ने बादिले नाख़्वास्ता नमाज़ पढ़ानी शुरू की, और हुज़ूर की ज़िंदगी में उन्होंने 17 नमाज़ें पढ़ाईं, जुमरात के दिन इशा की नमाज़, जुमा की 5 नमाज़ें, सनीचर की 5 नमाज़ें, इतवार की 5 नमाज़ें, फिर पीर के दिन फ़ज्र की नमाज़, इन सब नमाज़ों में पैग़म्बर अ़लैहिस्सलाम पर ज़ोफ़ इस क़द्र तारी था कि आप मस्जिद में तशरीफ़ नहीं ला सके, पीर के रोज़ आप ने थोड़ा सा परदा हटाया, सहाबा रज़ि अल्लाहु अ़न्हुम फ़रमाते हैं कि वह मंज़र बड़ा अजीब था जो कभी भुलाया नहीं जा सकता कि आप का चेहरा-ए-अनवर ऐसे चमक रहा था जैसे क़ुरआने पाक का कोई वरक़, और सहाबा को बेहद ख़ुशी थी कि हज़रत ग़ालिबन रूबसेहत हो गए, लेकिन फिर आप ने परदा छोड़ दिया। (अल रौज़फ़ल अनफ़ 4/439) और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ि अल्लाहु अ़न्हा से फ़रमाया कि ख़ैबर के मौक़े पर एक यहूदी औरत ने मुझे ज़हर खिला दिया था, अब मैं उस का असर महसूस कर रहा हूँ, और मुझे अंदेशा है कि यह जान लेवा साबित होगा, बहर हाल पीर के रोज़ तबीयत में थोड़ी बशाशत थी लेकिन जैसे जैसे वक़्त आगे बढ़ा, आप का ज़ोफ़ भी बढ़ता रहा। (बुख़ारी शरीफ़ 2/637)

सानिहा-ए-वफ़ात

हज़रत आइशा सिद्दीक़ा रज़ि अल्लाहु अ़न्हा फ़रमाती हैं कि हुज़ूर का सर मेरी गोद में रखा हुआ था और आप फ़रमा रहे थे:

ऐ अल्लाह मौत की सख़्तियों पर मेरी मदद फ़रमा।

इसी तरह आप यह भी फ़रमा रहे थे:

ऐ अल्लाह मैं रफ़ीक़े आला को इख़्तियार करता हूँ।

हज़रत आइशा सिद्दीक़ा रज़ि अल्लाहु अ़न्हा फ़रमाती हैं कि पैग़म्बर अ़लैहिस्सलाम फ़रमाते थे कि जब किसी नबी की वफ़ात का वक़्तख़ क़रीब आता है, तो उस से बतौर ऐज़ाज़ पूछा जाता है कि आप की विसाले रब के बारे में क्या राय है? हज़रत आइशा सिद्दीक़ा रज़ि अल्लाहु अ़न्हा फ़रमाती हैं कि जब मैंने यह सुना, तो मुझे यक़ीन हो गया कि अब अल्लाह तआ़ला ने आप को अपने दरबार में बुलाने का फ़ैसला फ़रमा लिया है। (जारी)

यूपी ही नहीं, राजस्थान को भी रोज़गार चाहिए छत्तीसगढ़ की लड़कियां भी चाहंती हैं स्कूटी

अतुल अंजान

वामदल राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के ख़िलाफ़ खिंचते दो पालों में किसी को बहुत भरोसे के साथ नहीं देख रहे हैं। वे न तो ममता के साथ अपने को सहज पा रहे हैं और न ही कांग्रेस से उन्हें सुकून मिल रहा है। इस बीच पांच राज्यों के चुनाव में अपने लिए स्पेस तैयार करने की फिक्र भी बढ़ी है। वे मानते है। कि इन राज्यों में उनके ज़रिए कोई बड़ा उलटफेर नहीं होने वाला लेकिन इन राज्यों के नतीजों के ज़रिए 2024 के लिए देश की सियासत के नए समीकरण ज़रूर गढ़े जाएंगे। एक इंटरव्यूह के दौरान भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अतुल अंजान से बात कर जानना चाहा वामदलों का नज़रिया। पेश है अनजान जी से बातचीत के प्रमुख अंश।

सवालः- इस तरह की ख़बरों पढ़ने को मिल रही हैं कि पांच राज्यों के चुनाव में वामदल भी हाथ आज़माने की तैयारी में है?

जवाबः- राजनीतिक दल होने के नाते हमें अधिकार है किसी भी राज्य में चुनाव लड़ने का। जिन पांच राज्यों में चुनाव होने हैं, उनकी विधानसभाओं में हमारी नुमाइन्दगी नही है लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं है कि हमने उन राज्यों में जनता के मूलभूत सवालों पर लड़ाई बंद कर दी है।

सवालः- अकेले चुनाव लड़ने का इरादा है या फिर राज्यों में जो ग़ैर भाजपा गठबंधन बन रहे हैं, उनमें शामिल होंगे?

जवाबः- यह ठीक है कि भाजपा हमें स्वीकार्य नहीं लेकिन भाजपा को हराने के लिए हम उन दलों को भी स्वीकार नहीं कर सकते जिनका हमारे साथ कोई वैचारिक एका नही हैं। पहली कोशिश तो यह है कि समान विचार धारा वाले दलों के साथ बात बन जाए। बन जाती है तो मिल कर लड़ेंगे वर्ना अकेले लड़ेंगे।

सवालः- जिन पांच राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उनमें आप लोग अपनी क्या राजनीतिक स्थिति आंकते हैं?

जवाबः- ऐसे तो बिहार के लिए भी यह कहा जाता था कि वामदलों की वहां कोई हैसियत नहीं, वे ख़त्म हो गए हैं लेकिन जब भाजपा को हराने के लिए महागठबंधन की ज़रूरत पड़ी तो सभी को वामदल याद आए। वामदलों के ज़रिए महागठबंधन को कितना फायदा हुआ यह बिहार में महागठबंधन में शामिल दलों के नेताओं से पूछिए।

सवालः- राष्ट्रीय स्तर पर नरेन्द्र मोदी के ख़िलाफ़ दो पाले खिंच रहे हैं एक सोनिया गांधी के नेतृत्व में और दूसरा ममता बनर्जी के, आप लोग किसके साथ रहना चाहेंगे?

जवाबः- पिछले साढ़े सात साल के दौरान चेहरे की राजनीति से देश का बहुत नुकसान हुआ है। अब हमें चेहरे की राजनीति नहीं चाहिए, हमें नीतियों चाहिए।

सवालः- तो किसकी नीतियां बेहतर है ममता की या सोनिया गांधी की?

जवाबः- इन दोनों की नीतियां स्पष्ट है। कांग्रेस आज यूपी में रोज़गार की मांग कर रही है तो यह वह मांग राजस्थान के लिए क्यों नहीं कर रही है? क्या राजस्थान में रोज़गार की कोई ज़रूरत नहीं है या वहां रोज़गार की मांग कर अपनी सरकार को परेशान नहीं करना चाहती? अगर यूपी में 40 प्रतिशत महिलाओं को टिकट दिया जा सकता है तो पंजाब में क्यों नहीं दिया जा सकता? क्या वहां महिलाओं के सशक्तीकरण की कोई ज़रूरत नहीं? अगर यूपी की लड़कियों को स्कूटी देने का वादा हो सकता है तो छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं दी जा सकती स्कूटी? वहां तो उनकी अपनी सरकार है। रही बात ममता की तो वह बताएं न कि 11 वर्ष से सीएम हैं, उनकी क्या नीतियां हैं? सिर्फ दिल्ली आकर मीडिया में अपने लिए जगह बना लेना काफी नहीं है। इसे किसी पॉलिटिकल पार्टी की नीति नहीं कहा जा सकता।

सवालः- 2024 के चुनाव में आप लोग किसके पाले में दिखना चाहेंगे?

जवाबः- एक अंग्रेजी कहावत का हिन्दी अनुवाद है कि आप पुल तब पार करते हैं जब आप पुल पर पहुंचते हैं। इन पांच राज्यों के चुनाव हो जाने दीजिए। नतीजों के ज़रिए देश की सियासत में नए समीकरण बनते दिखेंगे। 2024 तो बहुत दूर है, आपको देश की सियासत में बहुत सारा बदलाव 2022 में ही देखने को मिल जाएगा।

सवालः- वैसे आप लोगों ने कभी इस बात पर ग़ौर किया कि हिन्दी बेल्ट से आप लोग ख़त्म क्यों हो गए?

जवाबः- हम लोगों को पता है। मंडल-कमंडल और मंदिर मस्जिद की लड़ाई ने हमारा बहुत नुकसान किया है। हम न तो मंदिर के पाले में खड़े हो सकते हैं न ही मस्जिद के। हम संविधान के साथ खड़े रहे। आज भी उसी पाले में हैं और आगे भी रहेंगे।

सवालः- हिन्दी भाषी राज्यों की पॉलिटिक्स तो वहीं की वहीं खड़ी है?

जवाबः- मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर लड़ा जाने वाला यह आख़िरी चुनाव होगा। धर्म का जुनून ख़त्म होगा। बेरोज़गारी की मार कब तक लोग झेलेंगे? वह सरकारों से सवाल पूछना शुरू करेंगे कि हमारे लिए रोज़गार कहां हैं, हमारे लिए अस्पताल कहां हैं, हमारे लिए स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय कहां हैं?

सवालः- वैसे पांच राज्यों का क्या चुनावी परिदृश्य आप लोग देख रहे हैं?

जवाबः- पाँच राज्यों के चुनावी परिदृश्य देखने के बजाय हम इन राज्यों के मतदाताओं से कह रहे हैं कि आप देश का परिदृश्य देखिए। देश कहां से कहां पहुंच गया है। अगर वक़्त रहते नहीं चेते तो देश को बड़ी कीमत चुकानी पड़ जाएगी। ❑❑

फौज के बल पर पूर्वोत्तर में अलगाववाद कभी ख़त्म नहीं हो सकता

के॰ संगमा

मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के. संगमा नेशनल पीपल्स पार्टी (एनपीपी) के मुखिया हैं। एनपीपी एनडीए की घटक है और मेघालय तथा मणिपुर में उसकी भाजपा के साथ साझा सरकार है। फिर भी संगमा नागरिकता (संशोधन) कानून 2019 और सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) कानून, 1958 (एएफएसपीए) वगैरह पर भाजपा के ख़िलाफ़ सख़्त रुख़ ज़ाहिर करते रहे है। एएफएसपीए को रद्द करने की मांग पूर्वोत्तर के कई राज्यों में काफी पहले से ही हो रहे हैं। नागलैंड में बीते वर्ष 04 दिसंबर को सेना की कार्रवाई में 14 आम लोगों के मारे जाने के बाद संगमा ने एएफएसपीए के खिलाफ़ फिर अपनी आवाज़ बुलंद कर दी। पेश है संगमा जी से एक बातचीत के प्रमुख अंश।

सवालः- आप एएफएसपीए को ख़त्म करने की मांग क्यों कर रहे हैं?

जवाबः- हमने कोई पहली बार एएफएसपीए को ख़त्म करने की मांग नहीं की है। हमारी पार्टी पिछले 20 साल से यह मांग कर रही है। पूर्वोत्तर में अलगाववाद पेचीदा सामाजिक आर्थिक मसला है। कानून व्यवस्था की समस्या तो इसी पेचीदगी से पैदा होती आई है। किसी सामाजिक आर्थिक समस्या का हल हम फौजी ताक़त से नहीं कर सकते। हमें ताक़त की दरकार है, मगर इस तरह की नहीं।

सवालः- सशस्त्र बलों की दलील है कि एएफएसपीए ज़रूरी है क्योंकि अलगाववाद ज़रूरी है क्योंकि अलगाववादी विरोधी अभियान युद्ध जैसे हालात में चलाए जाते हैं..?

जवाबः- अगर सामाजिक-आर्थिक उपद्रवों से युद्ध की तरह निबटते हैं और सेना उतार देते हैं तो यह ग़लत दिशा में उठा क़दम है। ज़रूरी हो तो ताक़त के इस्तेमाल की दरगार है, लेकिन इस तरह ताक़त के इस्तेमाल से कोई स्थायी हल नहीं निकलेगा। ताक़त के बर्बरतापूर्ण इस्तेमाल का बुरा असर होता है। हम पहले भी बहुत से बेकसूरों को जान गंवाते देख चुके हैं।

सवालः- नगालैंड में अलगाववाद पूर्वोत्तर के दूसरे राज्यों के मुक़ाबले कहीं लंबा और गंभीर मुद्दा रहा है। कई लोगों का कहना है कि एएफएसपीए की वजह से वहां हिंसा में काफी कमी आई है.?

जवाबः- नगालैंड में अलगाववाद ज़्यादा गंभीर हो सकता है मगर एएफएसपीए से कोई मदद नहीं मिलने वाली, जैसा कि पिछले छह दशक के अनुभवों से साफ है। सशस्त्र बलों का योगदान कानून व्यवस्था की स्थिति संभालने में रहा है। लेकिन आजकल सेना का इस्तेमाल जिस रूप में किया जा रहा है, यानि बिना जवाबदेही के कुछ भी करने का खुला अधिकार दे दिया गया है, ऐसा तो भारत जैसे सभ्य और लोकतांत्रिक देश में जारी नहीं रह सकता। ऐसे डरावने क़ानूनों पर अमल के बग़ैर भी अलगाववाद से निबटने के लिए हमारे पास पर्याप्त टेक्नोलॉजी, खुफिया और पुलिस तंत्र है। हमें दूसरे पक्ष को देश का दुश्मन मानने के बदले मानवीय तरीक़े तलाशने की ज़रूरत है।

प्रश्नः- मेघालय में एएफएसपीए लागू नहीं है। क्या आप यह मांग इसलिए कर रहे हैं, ताकि नगालैंड में अपना राजनैतिक आधार फैला सकें और वहां के लोगों की भावनाओं का दोहन कर सकें.?

जवाबः- हमारी पार्टी पूर्वोत्तर के लोगों से जुड़े मुद्दों के हक़ में खड़ी है। हमें लोगों का समर्थन हासिल है और हम उनका ज़्यादा समर्थन हासिल करना चाहते हैं, ताकि हम इस क्षेत्र की तरक़्क़ी में ज़्यादा से ज़्यादा योगदान कर सकें। हम निश्चित रूप से पूर्वोत्तर में अपना आधार बढ़ाना चाहते हैं लेकिन मैं एएफएसपीए का मुद्दा पहली बार नहीं उठा रहा हूं। हमने 2002 में मणिपुर विधानसभा चुनावों के दौरान एएफएसपीए के ख़ात्मे की मांग उठाई थी।

प्रश्नः- आप सीएए और एएफएसपीए के ख़िलाफ हैं, जबकि भाजपा की अगुआई वाली केन्द्र सरकार दोनों कानूनों हक़ में हैं आप मेघालय और मणिपुर में भाजपा के साथ सरकार में हैं लेकिन अरुणाचल प्रदेश में उनके ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, इसे विरोधाभास के क्या मायने हैं.?

जवाबः- हमारी अपनी राजनैतिक पहचान और विचारधारा है। सीएए और एएफएससीए जैसे मुद्दों पर जहां असहमति है हम भाजपा के ख़िलाफ खड़े हैं अगर पूरी सहमति होती तो हमारी पार्टी का भाजपा में विलय न हो गया होता। ज़रूरत इस बात की है कि लोगों के हित को ध्यान में रखकर एक साथ काम किया जाए। राजनैतिक गठजोड़ का मकसद मतभेद और सहमति के बीच तालमेल बिठाना होता है। कई मुद्दों पर दो पार्टियों की राय एक हो सकती है। ❑❑

सेवा करने के लिए कुर्सी ही ज़रूरी क्यों?

हमारे देश की बहुत बड़ी त्रासदी है कि हमारे देश के लगभग सभी नेता जनता की सेवा करना चाहते हैं लेकिन बेचारे कर नहीं पाते क्योंकि बीच में कुर्सी की समस्या आ जाती है। कुर्सी से मतलब उनको कोई न कोई पदभार चाहिए, जैसे चेयरमैनशिप, मंत्री पद, मुख्यमंत्री पद या कोई प्रधानगी वाला ओहदा, जहां उनको सरकारी फंड बांटने व ख़र्च करने का अधिकार मिल सके। तभी उनकी जनसेवा वाली भावना के सामने वाला अवरोध हट सकता है। बिना किसी पद के ऐसे मजबूर हो जाते हैं जैसे 'शोले' में ठाकुर अपने सामने ज़मीन पर पड़ी बंदूक नहीं उठा पाने में असमर्थता दिखाता था क्योंकि अपने दोनों हाथ कटे जोने की वजह से वह मजबूर था।

नव वर्ष 2022 में अब आ चुके हैं और हर ओर नई चर्चाएं हैं, पर एक चर्चा है बीते वर्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने एक प्रैस कांफ्रेंस के दौरान के बयान दिया कि वह पहले 40 करोड़ कमाते थे, अब चालीस हजार कमा रहे हैं लेकिन 40 हजार भी उनके लिए 4 लाख करोड़ से बढ़कर हैं क्योंकि वह पंजाब की जनता की सेवा के लिए मिल रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब की औरतें स्वाभिमानी हैं, वे केजरीवाल के दिए 1000 रुपए की खैरात कभी स्वीकार नहीं करेंगी। अगर उनकी पत्नी को हजार मिले तो वह वापस फेंक देंगी।

उन्होंने केजरीवाल से प्रश्न भी किया कि वह दिल्ली की महिलाओं को 1000 रुपए प्रतिमाह क्यों नहीं दे रहे। क्या वह पंजाब में केवल चुनाव जीतने के लिए ऐसे लुभावने वादे कर रहे हैं? साथ ही उन्होंने पूछा कि इसके लिए पैसा कहां से आएगा, खज़ाना तो पहले ही ख़ाली है। जब से पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनी है तब से सिद्धू भी इस सरकार का हिस्सा रहे हैं, लेकिन वह कभी अपनों से तो कभी विरोधियों से ही उलझे रहे और पंजाब की समस्याओं को हल करने पर कभी ध्यान नहीं दिया क्योंकि उनके पास 'कुर्सी' नहीं थी। जिस कुर्सी की उन्हें आस थी, वह ''चन्नी'' के पास चली गई। कुर्सी मिलते ही चन्नी जी जनता की धड़ाधड़ सेवा किए जा रहे हैं क्योंकि शायद वह जानते हैं कि इस बसंत की ऋतु बहुत छोटी है। शायद फिर कभी मौक़ा मिले या न मिले। इसलिए जनता की जितनी सेवा कर सकते हैं कर ली जाए। जगह-जगह बड़े बड़े बैनर लगा कर यह स्लोगन भी हाई लाइट किया जा रहा है :

'घर घर दे विच चल्ली गल्ल
चन्नी करदा मसले हर'

बादल परिवार भी जनता की सेवा का मौक़ा ढूंढ रहा है। योगी जी, अखिलेश यादव, मायावती जी, लालू जी, अर्थात् हमारे देश में जितने भी नेता हैं, सभी जनता की जी-जान से सेवा करना चाहते हैं, इनमें से कई करोड़पति या अरबपति भी हैं। ये अपने पैसों से सेवा नहीं करना चाहते, बल्कि सरकारी खज़ाने से ही हम सबकी सेवा करना चाहते हैं। इसके लिए इनको अच्छा सरकारी 'पद' चाहिए। ये लोग हमारी सेवा के इतने शौकीन हैं कि चुनाव लड़ने के लिए लाखों करोड़ों पानी की तरह बहा देते हैं।

इनका तो एक ही उद्देश्य है कि गरीब जनता का जीवन स्तर 'ऊंचा' उठा दिया जाए। मिडल क्लास को नौकरियां दे दी जाएं। गांवों को शहरी जैसा और शहरों को विदेशों जैसे खूबसूरत बना दिया जाए। यह अलग बात है कि शहरों में मूलभूत सुविधाओं तक का बेड़ागर्क हुआ पड़ा है। ज़्यादातर सड़कें टूटीं हुई हैं, कहीं पानी की समस्या है, कहीं ट्रैफिक की, कहीं सांस लेने के लिए शुद्ध हवा नहीं मिल पा रही है, कहीं सीवरेज जाम हो रहा है, कहीं बिजली की समस्या है। शहर चाहे सुंदर बन पाए या नहीं, लेकिन इनके घर ज़रूर विदेशी घरों जैसे खूबसूरत बन गए हैं और हर लग्जरी आइटम्स व सुविधाओं से सुसज्जित हैं।

आम जनता की जीवन यापन वाली गाड़ी चाहे खटारा हालत में चल रही हो, लेकिन इनकी सेवा में दो-चार गाड़ियां हरदम तैयार रहती हैं। रहें भी क्यों न, आख़िर इनके बिना हमारा भी गुज़ारा कहां हैं। कोई भी समस्या हो, हम लोग उसका समाधान करवाने के लिए इनके पास ही भागते हैं, जब इनके पास 'सत्ता' होगी तभी ये लोग ठीक से हमारी समस्या का 'समाधान' कर पाएंगे।

अब न शहीद-ए-आज़म भगत सिंह जैसे आज़ादी के परवाने बचे हैं, जो देश के लिए हंसते-हंसते फांसी का फंदा चूम कर मौत को गले लगा लेते थे, न रानी लक्ष्मी बाई जैसी वीरांगनाएं हैं, जो मात्र 29 वर्ष की आयु में अपनी झांसी को बचाने के लिए अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को अपनी पीठ पर बांध कर अंग्रेजों

बाक़ी पेज 11 पर

रोज़गार .....

बैंकिंग और फाइनेंस में कैरिअर की राह

आज भारत में बैंकिंग सेक्टर का इतना विस्तार हो गया है कि वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों की 67 हज़ार से अधिक शाखाएं काम कर रही हैं। ऐसी उम्मीद की जा रही हैं कि 2040 तक भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा बैंकिंग हब बन जाएगा। ख़बर यह है कि साल के अंत तक तकरीबन 40 हजार लोग रिटायर भी हो सकते हैं। इनमें हर सेक्टर के लिए अलग अलग कर्मचारियों की मांग है। जैसे इंटरनेशनल बैंकिंग के सेक्टर एनआरआई बैंकिंग ऑफिसर, इंटरनेशनल ट्रेड, ऑफिसर, फोरेक्स ऑफिसर।

बिजनेस बैंकिंग के सेक्टर में कॉपोरेट बैंकिंग आफिसर, क्रेडिट ऑफिसर, कैश मैनेजमंट आफिसर। फाइनेंशियल रिसर्च के सेक्टर में फाइनेंशियल एनालिस्ट, इक्विटी रिसर्च एनालिट। ब्रांच बैंकिंग के सेक्टर में पर्सनल बैंकर, वेल्थ एडवाइजर, लोन ऑफिसर के लिए विकल्पों की भरमार हैं एचडीएफ सी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचएसबीसी, कोटक महिन्द्र बैंक जैसे निजी बैंक हैं, वहीं सरकारी बैंकों ने भी युवाओं के लिए ढेरों अवसर तैयार किए हैं। इसी के मद्देनज़र अब सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और पीजी डिप्लोमा जैसे कुछ प्रोफेशनल कोर्स भी प्रचलन में आ गए हैं। ये कोर्स प्राइवेट बैंकों में कैरिअर की राह, आसान तो करते ही हैं सरकारी बैंकों में भी पीओ, क्लर्क, आरबीआई ऑफिसर्स की तैयारी कर रहे छात्रों को भी बैंकिंग की बारीकियां जानने का मौक़ा देते हैं।

अलग-अलग सेक्टर्स का कार्य

एनआरआई बैंकिंग ऑफिसर भारत या विभिन्न देशों की विदेशी शाखाओं में स्थानीय शाखाओं से बैंक के एनआरआई ग्राहकों को संभालने की ज़िम्मेदारी होती हैं बैंकिंग परिचालन और विदेशी मुद्रा सेवाओं के अलावा वे इन एनआरआई ग्राहकों के लिए भारत में निवेश सलाहकार के रूप में भी काम करते हैं।

इंटरनेशनल ट्रेड ऑफिसर

इंटरनेशनल ट्रेड ऑफिसर का काम व्यापार का विकास और दो देशों के बीच गुड्स एण्ड सर्विसेज के लेन-देन और गठजोड़ को बढ़ावा देना होता हैं जिस कंपनी के लिए आप काम कर रहे हैं उस पर ग्लोबलाइजेशन का क्या प्रभाव पड़ रहा है यह भी देखना अधिकारी की ज़िम्मेदारी होती है।

फोरेक्स ऑफिसर

फोरेक्स ऑफिसर बैंकों और ग्राहकों की तरफ से विभिन्न और विदेशी मुद्राओं की लेन-देन को संभालने का काम करते हैं। जब कोई बैंक ग्राहक विदेशी मुद्रा को खरीदना या बेचना चाहता है तब उस मुद्रा का सही मूल्य ग्राहक को समझाने का काम भी फोरेक्स ऑफिसर का होता है।

कॉपोरेट बैंकिंग ऑफिसर

कॉपोरेट बैंकिंग ऑफिसर व्यापार और बड़ी कंपनियों के ग्राहकों के लिए नियमित रूप से बैंकिंग परिचालन में विशेष रूप से डिजाइन के उत्पाद उपलब्ध कराने का काम करता है। यह सैलरी और करंट अकाउंट वाले ग्राहकों से भी अच्छे संबंध बनाये रखने के लिए भी ज़िम्मेदार होता है। इसके अलावा इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, क्रेडिट रिसर्च एनालिस्ट, पर्सनल बैंकर, वेल्थ एडवाइजर, लोन ऑपिसर, क्रेडिट ऑफिसर कैश मैनेजमेंट ऑफिसर एवं फाइनेंशियल एनालिस्ट पद के हैं।

पाठयक्रम के बारे में

टीकेडब्लूएस इंस्टीटयूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनेंस के डायरेक्टर के मुताबिक ग्लोबल पीजी डिप्लोमा इन बैंकिंग एण्ड फाइनेंस एक वर्ष का कोर्स है। इसके तहत बैंकिंग ऑपरेंशस, धन प्रबंधन, ट्रेड फाइनेंस, फोरेक्स, फाइनेंस एसएमई जैसे विषय पढ़ाया व सिखाया जाता है।

योग्यता

स्नातक और किसी भी स्ट्रीम से अंतिम वर्ष के छात्र इस कोर्स में आवेदन कर सकते हैं। जिन विद्यार्थी के स्नातक में कम से कम 50 प्रतिशत है वह भी इस कोर्स में आसानी से आवेदन कर सकते हैं।

कैरिअर और प्लेसमेंट

इस कोर्स के ख़त्म होने के बाद विद्यार्थी को इंटरनेशनल बैंकिंग, फोरेक्स और ट्रेजरी, कापोरेट, लोंस, फाइनेंशियल रिसर्च संबंधित बड़ी ब्रांडों से ऑफर मिलने लगते हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय बैंक्स अलग अलग स्किल्स के बच्चों को अच्छी सैलरी पर नियुक्त करते हैं। सार्वजनिक बैंक ज़्यादातर अखिल भारतीय स्तर पर परीक्षा के आधार पर क्लर्क और परिवीक्षाधीन अधिकारी के पदों के लिए नियुक्तियां करते हैं।

प्रमुख संस्थान

इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली www.ignou.nic

इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली। www.ipu.ac.in

टीकेडब्ल्यूएस इंस्टीटयूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनेंस, नई दिल्ली। www.tkwsibf.org

मणिपाल यूनिवर्सिटी, कर्नाटक www.manipal.edu

सिम्बोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, मुम्बई, महाराष्ट्र। www.siu.edu.in ❑❑

इस्लामी दुनिया

दुकानों पर मॉडल- पुतले ग़ैर इस्लामी : तालिबान

काबुल : अफग़ानिस्तान के बल्ख प्रांत में सामूहिक हम्मामों में महिलाओं के नहाने से इंकार करने और काबुल की नहर में 3000 लीटर शराब बहाने के बाद तालिबान ने नया फरमान जारी किया है। उसने दुकानों पर लगे मॉडलों के पुतलों को ग़ैर कानूनी बताकर उन्हें हटाने का आदेश दिया। हेरात प्रांत के एक वीडिया में दिख रहा है कि इन पुतलों के सिर तोड़ते हुए वहां खड़े कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। पुतलों के सिर काटने का आदेश तालिबान सरकार ने जारी किया और इन पुतलों में से हरेक की कीमत 70 से 100 डॉलर थी।

पाक के सिंध में हिन्दू व्यवसायी की हत्या

सिंध : पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अनाज मंडी के पास अज्ञात लोगों ने 44 वर्ष के हिन्दू व्यवसायी सुनील कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी। इस फायरिंग के बाद शहर को बंद कराने का ऐलान किया गया। हत्यारों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर एक स्थानीय पुलिस स्टेशन के पास लोगों ने 2 जनवरी को धरना भी दिया। यह हमला अल्पसंख्यक, विशेषकर हिन्दुओं, अहमदिया व इसाईयों के ख़िलाफ़ अत्याचार का एक उदाहरण है।

इस्राईल ने परमाणु हथियारों में पाक को मदद कर रही कंपनियों पर गिराए थे बम

येरुशलम: इस्राईल के प्रमुख दैनिक ने बताया है कि देश की जासूसी एजेंसी मोसाद पर पाकिस्तान के परमाणु हथियार कार्यक्रम में मदद करने वाली जर्मनी और स्विस कंपनियों पर बम गिराने और धमकाने का संदेह है। यह मामला 1980 के दशक का है जब इस यहूदी देश के एटमी क्षमता हासिल करने पर पाक को ख़तरे के रूप में पाया था। पाकिस्तान ने पहली बार एटम बम के साथ इस्लामी राष्ट्र बनने की संभावना ने इस्राईल के अस्तित्व के लिए ख़तरा पैदा किया था।

इमरान को तलब करने की चेतावनी

पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश गुलज़ार अहमद ने चेतावनी दी है के क़ैदी को हिरासत केन्द्र से शीर्ष न्यायालय में पेश नहीं किया जाता है तो इमरान ख़ान को तलब किया जा सकता है। अहमद की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने अफग़ानिस्तान सीमा के पास सैन्य शिविर पर हमले के आरोपी आरिफ गुल की हिरासत के ख़िलाफ़ सुनवाई के दौरान यह कहा। जस्टिस गुलजार अहमद ने अटार्नी जनरल से पूछा क्या वह आरोपी को लाए हैं तब उन्होंने कहा, गुल हिरासत केंद्र में हैं गुलजार ने कहा, उसे न पेश किया जाए तो अदालतों को सील कर दीजिए। हमारे पास नेतृत्व को तलब करने की भी शक्ति है।

अवसाद में घिरता बचपन

ज्योति सिडाना

कहते हैं कि जिसे जिना आता है, वह बिना किसी सुविधा के भी खुश मिलेगा। जिसे जीना नहीं आता, वह सभी सुविधाओं के होते हुए भी दुखी मिलेगा। यानि ख़ुश रहने के लिए सामान की नहीं, सम्मान की आवश्यकता होती है। आज विश्व के लगभग हर देश और समाज में अवसाद, तनाव, क्रोध, हिंसा, उदासी, निराशा का स्वर बढ़ता देखा जा सकता है। प्रश्न है कि क्यों हो रहा है ऐसा? यह सच है कि सुख-दुख, आशा निराशा, हंसी क्रोध जैसे भाव साथ साथ चलते है और हर किसी को इनका सामना कभी न कभी करना पड़ता है, लेकिन जो विपरीत स्थिति में भी संतुलित व्यवहार करे, धैर्स से सामना करे उसे मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति कैसे माना जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य एक ऐसी स्थिति है, जिसमें किसी व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का एहसास रहता है, वह जीवन के सामान्य तनावों का सामना कर सकता है, लाभकारी और उपयोगी रूप से काम कर सकता है और अपने समाज के प्रति योगदान करने में सक्षम होता है।

हाल ही में बच्चों-किशोरों पर किए गए एक सर्वेक्षण में सामने आया है कि सभी विद्यार्थी मानसिक रूप से स्वस्थ होने का अर्थ जानते हैं और इसके लक्षण भी, लेकिन इसके बावजूद पिछले कुछ समय से अनेक युवा मानसिक रूप से अस्थिर बने हुए हैं। परीक्षाओं का समय पर न होना, अनिश्चितता की स्थिति, अगली कक्षा में प्रोन्नत होने के बाद भी कक्षाओं को नियमित रूप से न लग पाना आदि ऐसे अनेक कारण है, जिनकी वजह से वे अपने भविष्य को लेकर असुरक्षित अनुभव करते हैं। पहले से ही बेरोज़गारी का आंकड़ा काफी व्यापक है, अगर यही हाल रहा तो उन्हें डर है कि उनका जीवन अंधकारमय होगा। इसी डर से वे मानसिक रूप से अस्वस्थ हो रहे हैं और अनेक मानसिक विकारों, क्रोध, जैसे लक्षणों से घिरे दिखाई दे रहे हैं। जब उन्हें कोई रास्ता सुझाई नहीं देता, तो आत्महत्या जैसे कठोर क़दम उठाने से भी नहीं हिचकते।

यह भी एक तथ्य है कि आज के दौर में भी लोग मनोचिकित्सक के पास जाने से झिझक महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि वही लोग मनोचिकित्सक के पास जाते हैं, जो मानसिक रोगी होते है। या फिर वे इस बात से डरते हैं कि दूसरों को पता लगेगा कि वह मनोचिकित्सक के पास गया था, तो वे उनके बारे में क्या सोचेंगे। भारत जैसे देश में शायद पहले के समाज में मनोचिकित्सक की इतनी आवश्यकता नहीं होती थी, क्योंकि संयुक्त परिवार हुआ करते थे। लोगों में घनिष्ठ और अनौपचारिक संबंध होने के कारण वे एक दूसरे से अपनी सारी बातें साझा कर लेते थे। किसी भी समस्या का सामना सामूहिक आधार पर ही हो जाता था, किसी भी समस्या के आने पर यह सुनना कि घबराओ मत, हम हैं न, सब ठीक हो जाएगा - हर प्रकार के तनाव को समाप्त कर देता था।

पर आज व्यक्तिवादिता इतनी हावी हो चुकी है कि अपने सामने कोई और दिखाई ही नहीं देता। परिवारों में भी 'हम' का स्थान 'मैं' ने ले लिया है। यही कारण है कि किसी भी समस्या का सामना अब अकेले ही करना पड़ता है, जो व्यक्ति को, विशेष रूप से किशोरों और युवाओं को मानसिक रूप से कमज़ोर कर देता है। अनुभवों की कमी के कारण वे संघर्ष से घबरा जाते हैं और नकारात्मकता उनके व्यक्तित्व का अभिन्न हिस्सा बन जाती है। आज के समय में अनेक सामाजिक और आर्थिक समस्याओं के साथ यह भी एक गंभीर चुनौती है, जिसका सामना करने के लिए न केवल चिंतन, बल्कि समय रहते तीव्र और उचित समाधान करने की ज़रूरत है।

डब्ल्यूएचओ की मानें, तो वैसे ही सामान्य अवस्था में हर पांचवां भारतीय किसी न किसी मानसिक समस्या से जूझ रहा होता है। ऐसे में कोरोना के कारण हर आयु और वर्ग के लोगों में विभिन्न मानसिक समस्याओं ने दोगुना प्रभाव डाला है। एक रिपोर्ट के अनुसार बच्चों मेमं 2019 की तुलना में 2020 में पारिवारिक कारणों से आत्महत्या के मामले दोगुने हुए हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में देशभर में 18 वर्ष से कम आयु के 11,396 बच्चों ने आत्महत्या की। ऐसे में यह और भी चिंताजनक स्थिति है कि भारत अपने स्वास्थ्य बजट का मात्र 1.3 प्रतिशत भाग मानसिक स्वास्थ्य पर व्यय करता है, जो कि पर्याप्त नहीं कहा जा सकता। सरकार को मानसिक स्वास्थ्य के बजट में वृद्धि करनी होगी अन्यथा इस समस्या से निपटना सहज नहीं है।

इस दिशा में समाज, परिवार, सरकार और शिक्षण संस्थानों को मिलकर गंभीर प्रयास करने होंगे। स्कूलों-कॉलेजों में मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य विषय पर भी काम करने की ज़रूरत है। उनमें समय-समय पर मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिकों की सहायता से कार्यशाला/सेमिनार आयोजित करने की आवश्यकता है। हर स्कूल-कॉलेज में एक परामर्श केन्द्र अवश्य होना चाहिए, ताकि विद्यार्थी बिना झिझक वहां जाकर अपनी समस्या साझा कर उचित सलाह प्राप्त कर सकें। समाज के अन्य नागरिकों को भी समय-समय पर विभिन्न सामुदायिक केन्द्रों, ग़ैर सरकारी संगठनों, सामाजिक क्लबों द्वारा इस तरह के परामर्श निशुल्क उपलब्ध कराए जाने चाहिए। जिस तरह विभिन्न शारीरिक बीमारियों के प्रति जागरुकता और उपचार के लिए समय-समय पर शिविर लगाए जाते हैं उसी तरह मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरुकता लाने और मानसिक विकारों के उपचार/समाधान पर भी चर्चा हेतु सार्वजनिक शिविर लगाए जाने चाहिए। जागरुकता की कमी की वजह से आज भी समाज के अधिकांश हिस्सों में लोग मानसिक विकारों को ऊपरी हवा या किसी बुरी आत्मा का साया या जादू टोना मान कर इसका इलाज ढूंढते हैं, और सारी ज़िन्दगी इस समस्या से बाहर नहीं आ पाते।

देखा जाए तो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों एक दूसरे के कारण और परिणाम हैं, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है या फिर स्वस्थ मन वाले व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा होता है क्योंकि ख़ुशी की शुरुआत सकारात्मक सोच से होती है। नकारात्मक दृष्टिकोण केवल निराशा और दुख का कारण होता है। अनेक चिकित्सा अनुसंधान भी यह सिद्ध कर चुके हैं कि अधिकांश शारीरिक बीमारियां भी मानसिक कारणों से ही होती हैं। यानि मानसिक शांति उत्तम स्वास्थ्य की पहली शर्त है। आज के समय में हम लोगों से बातचीत करने से बचते हैं और ज़्यादातर समय ऑनलाइन व्यस्त रहते हैं या फिर संदेशों द्वारा बातचीत करते हैं। दोनों ही स्थितियों में भावनात्मक लगाव की कमी होती है, जिसके कारण वे अपने मन का बोझ या परेशानी साझा नहीं कर पाते, केवल औपचारिकता निभाते हैं।

आज लोग खुलकर हंसना ही भूल गए हैं, जिसके कारण भी शरीर अनेक रोगों और तनावों से घिरा रहता है इसलिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि सुबह-सुबह पार्क में जाकर लाफिंग क्लब में शामिल हो जाइए, ताकि शरीर का हर अंग सही ढंग से सांस ले सके और शारीरिक और मानसिक तनाव दूर हो सके। कहते हैं, हंसी न केवल एक बेहतरीन दवा, बल्कि एक अच्छा व्यायाम भी है। हंसना, सकारात्मक सोच रखना, सुबह घूमना, योग और व्यायाम करना, संतुलित भोजना करना, परिवार, मित्रों और सहकर्मियों के साथ बातचीत करना, समस्याओं का साझा करना, अपने शौक के लिए समय निकालना आदि मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। किसी ने कहा भी है कि जब कुछ सेकेंड की मुस्कान से फोटो अच्छी आ सकती है, तो हमेशा मुस्कराने से ज़िन्दगी कितनी ख़ूबसूरत हो सकती है इसलिए खुश रहना, मुस्कुराना और सकारात्मक सोचन ही ज़िन्दादिली है।

देखा जाए तो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों एक दूसरे के कारण और परिणाम हैं, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है या फिर स्वस्थ मन वाले व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा होता है क्योंकि ख़ुशी की शुरुआत सकारात्मक सोच से होती है। नकारात्मक दृष्टिकोण केवल निराशा और दुख का कारण होता है। अनेक चिकित्सा अनुसंधान भी यह सिद्ध कर चुके हैं कि अधिकांश शारीरिक बीमारियां भी मानसिक कारणों से ही होती हैं। यानि मानसिक शांति उत्तम स्वास्थ्य की पहली शर्त है। आज के समय में हम लोगों से बातचीत करने से बचते हैं और ज़्यादातर समय ऑनलाइन व्यस्त रहते हैं या फिर संदेशों द्वारा बातचीत करते हैं। दोनों ही स्थितियों में भावनात्मक लगाव की कमी होती है।

जातिगत समीकरणों के विरुद्ध संघ की शपथ का भाजपा पर कितना असर

आलोक मेहता

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने इस सप्ताह चित्रकूट में एक शपथ लेने का आहवान किया। शपथ का अन्तिम अंश यह है में जाति, वर्ग, भाषा, पंथ के भेदभाव से ऊपर उठकर अपने हिन्दू समाज को समरस, सशक्त और अभेद्य बनाने के लिए पूरी शक्ति के साथ कार्य करूंगा। श्री भागवत ने इस शपथ में हिन्दू धर्म, संस्कृति और समाज के संरक्षण संवर्धन एवं सुरक्षा के लिए आजीवन कार्य करने की प्रतिज्ञा दिलवाते हुए संघ, जनता पार्टी और भाजपा के पूर्व शीर्ष नेता नानाजी देशमुख से प्रेरणा लेने का आग्रह किया। सरसंघचालक के इस अभियान और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की काशी विश्वनाथ में पूजा अर्चना, मंदिर के नए भव्य परिसर के कार्यक्रमों से यह अर्थ लगाया गया कि अब भाजपा आगामी उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के विधान सभा चुनावों में बड़ी सफलता के लिए हिन्दू समाज, हिन्दुत्व को ज़ोर शोर से बढ़ाना चाहती है। यों कांग्रेस नेता रहुल गांधी ने भी अपने को असली हिन्दू बताकर भाजपा के हिन्दुत्व विचार को ख़तरनाक बताया है। लेकिन संघ संघ से जुड़ी भाजपा क्या सचमुच जातिगत समीकरणों से ऊपर चुनावी राजनीति कर पा रही है या आगामी लोकसभा चुनाव में भी इसे आदर्श आधार बना सकेगी? उत्तर प्रदेश और केन्द्रीय मंत्रिमंडल में कुछ समय पहले हुए विस्तार में तो भाजपा ने यह दिखाने की कोशिश की विभिन्न जातियों के नेताओं को प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। राहुल गांधी और अन्य कांग्रेसी नेताओं ने पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी को दलित मुख्यमंत्री के रूप में घोषित कर जातिगत समीकरणों को स्वीकार किया है।

पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में जाट, दलित और पिछड़ा - यादव, मुस्लिम वोट समीकरणों की चर्चा बनी हुई है। इस दृष्टि से संघ भाजपा के तेवर पर ध्यान दिया जाना स्वाभाविक है। लेकिन संघ, भाजपा की राजनीति को सालों से समझते रहने वाले हम जैसे पत्रकारों को लगता है कि भागवतजी ने अपने पूर्व प्रमुखों की बातों को सामने रखा है। अयोध्या, काशी मथुरा के मुद्दे भी नए नहीं है। इस संदर्भ में पूर्व भी नए नहीं है। इस संदर्भ में पूर्व सरसंघचालक प्रोफेसर राजेन्द्र सिंह द्वारा अक्तूबर 1997 में मुझे दिए एक इंटरव्यू का उल्लेख उचित होगा। उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में कहा था - हिन्दू समाज को संगठित करने के लिए हमारा प्रयास बराबर चल रहा है। राजनीति में जो लोग काम करते हैं, वे हमेशा तोड़ पैदा करते है। यदि तोड़ पैदा नहीं करेंगे तो वोट कैसे मिलेंगे? यह सच है कि जातिवाद, क्षेत्रवाद बढ़ा है क्योंकि हमारे देश में कई जातियां, भाषाएं हैं, लेकिन इन सबके बीच यानि उससे ऊपर हटकर संघ खड़ा है।

हम सबको संगठित करने का प्रयास करते रहेंगे। यह दुर्भाग्य की बात है कि देश के विभाजन के बाद भी हिन्दुत्व का भाव जितना बढ़ना चाहिए था नहीं बढ़ा है। राजेन्द्र सिंह ने इस इंटरव्यू में यह भी कहा था कि 'जो भी उच्च पद है, उनके लिए यह न कहा जाए कि हमारे राष्ट्रपति दलित हैं या हमारे मुख्य न्यायाधीश अमुक जाति के हैं या पार्टी के नेतृत्वकर्ता फलां जाति के हैं। हमें तो केवल यह कहना चाहिए कि यह व्यक्ति इस पद के लिए सबसे योग्य है। लेकिन हाल के सालों में अन्य दलों से मुक़ाबले के लिए भाजपा के कई नेता जातिगत वोटों और उम्मीदवारों को महत्व देने लगे हैं। दूसरी ओर संघ सरसंघचालक यह भी मानते रहे हैं कि भारत में जो मुसलमान हैं, उनमें से केवल दो प्रतिशत के पूर्व बाहर से आए थे, शेष 98 प्रतिशत के पूर्वज इसी देश के थे। उन्हें केवल यह अहसास करना है कि वे भारतीय मुसलमान हैं। उनकी पूजा पद्धति से कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि भारत में तो पहले से दर्जनों पूजा पद्धतियां हैं। इस तरह के आदर्शों के बावजूद चुनावी चक्कर में जिस तरह जिन्ना, औरंगज़ेब, पाकिस्तान, सार्वजनिक स्थानों पर नमाज़ या गौ रक्षा के नाम पर जब भाजपा का एक वर्ग मुस्लिम लोगों को निशाना बनाने की कोशिश करता है, तो सारी आचार संहिता अलग धरी रह जाती हैं। संभवत: यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अयोध्या, काशी की धार्मिक भावनाओं के साथ विकास योजनाओं, सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए हुए प्रयासों को महत्व देने का प्रयास करते हैं। चुनाव की आचार संहिता के अनुसार धार्मिक प्रचार तो नितांत अनुचित है। लेकिन हाल के सालों में पुरानी मुस्लिम लीग से बढ़कर असदुद्दीन औवेसी की पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही नहीं कुछ अन्य पार्टियाँ खुलकर धार्मिक गुरुओं, मौलानाओं, उपासना स्थलों को चुनाव में इस्तेमाल करने लगे हैं। इससे सामाजिक दूरियां कम होने के बजाय बढ़ने का ही ख़तरा रहता है। राहुल गांधी के 'हिन्दू' 'हिन्दूत्व' के नए राग एक पर कांग्रेस पार्टी के कई नेता असहमत हैं। राजीव गांधी के करीबी रहे वरिष्ठ नेता और राजनयिक मणिशंकर अय्यर तक ने पिछले दिनों मुझे इंडिया न्यूज़ के लिए दिए एक इंटरव्यू में माना था कि कांग्रेसियों द्वारा हिन्दू होने का दावा करने से कोई लाभ नहीं हो सकता, क्योंकि लोग हमें नकली हिन्दू मानेंगे।

यह दुर्भाग्य की बात है कि देश के विभाजन के बाद भी हिन्दुत्व का भाव जितना बढ़ना चाहिए था नहीं बढ़ा है। राजेन्द्र सिंह ने इस इंटरव्यू में यह भी कहा था कि 'जो भी उच्च पद है, उनके लिए यह न कहा जाए कि हमारे राष्ट्रपति दलित हैं या हमारे मुख्य न्यायाधीश अमुक जाति के हैं या पार्टी के नेतृत्वकर्ता फलां जाति के हैं। हमें तो केवल यह कहना चाहिए कि यह व्यक्ति इस पद के लिए सबसे योग्य है। लेकिन हाल के सालों में अन्य दलों से मुक़ाबले के लिए भाजपा के कई नेता जातिगत वोटों और उम्मीदवारों को महत्व देने लगे हैं। दूसरी ओर संघ सरसंघचालक यह भी मानते रहे हैं कि भारत में जो मुसलमान हैं, उनमें से केवल दो प्रतिशत के पूर्वज इसी देश के थे।

हमें अपने पुराने धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों पर ज़ोर देना चाहिए। लेकिन श्री अय्यर जैसे सहयोगियों की बात राहुल गांधी की टीम कहां सुनने वाली है। स्वस्थ सामाजिक वातावरण और जनता के असली दु:ख दर्द, आर्थिक परिस्थितियों में सुधार और लाभ को प्राथमिकता देने से ही लोकतंत्र अधिक सुरक्षित और लाभकारी हो सकेगा। तात्कालिक राजनीतिक स्वार्थो के लिए सामाजिक विद्वेष बढ़ाने पर राजनेताओं को ही दूरगामी नुकसान होने वाला है। यही नहीं चीन पाकिस्तान की सीमाओं पर तनाव, आतंकवादी हमलों और हथियारों के प्रबंध जैसे भारतीय सुरक्षा के मुद्दों पर भी ग़लत तथ्यों का राजनैतिक प्रचार का हिस्सा बनाने से सुरक्षा बलों की क्षमता पर भी अनावश्यक प्रश्न उठते हैं। इसलिए चुनावी दौर में विभिन्न दलों को अपनी रणनीति की आम समीक्षा भी करनी चाहिए।

रैली में बमुश्किल 700 लोगों के आने के कारण पीएम लौटे, सुरक्षा चूक का बनाया जा रहा बहाना: सीएम चन्नी

पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी ने कहा कि बीजेपी की रैली में बमुश्किल 700 लोग आए और इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 'अपना कदम वापस लेने' के लिए मजबूर होना पड़ा और बाद में सुरक्षा खतरों का हवाला देते हुए राज्य सरकार पर दोष मढ़ दिया गया। पंजाब की राष्ट्रवादी साख पर सवाल उठाने वालों को चुनौती देते हुए चन्नी ने स्पष्ट किया कि पंजाबी कभी भी देश के लिए बलिदान देने से पीछे नहीं हटे और देश में किसी अन्य की तरह देशभक्त हैं। प्रधानमंत्री द्वारा फिरोजपुर में भीड़ को संबोधित किए बिना ही वापस लौट जाने और फिर सुरक्षा में चूक का दावा करने वाली बुधवार की घटना का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री चन्नी ने माछीवारा कस्बे में कहा कि सच्चाग्र यह है कि रैली स्थल पर मुश्किल से 700 लोग ही पहुंचे थे, जिससे प्रधानमंत्री को वापस लौटना पड़ा। उन्होंने कहा कि सच्चाई यह है कि प्रधानमंत्री की निर्धारित रैली से पांच दिन पहले ही स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (एसपीजी) ने लैंलडग स्पॉट, रैली साइट और सुरक्षा डिटेल को अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन बाद में प्रधानमंत्री के काफिले ने अचानक लैंड रूट ले लिया। चन्नी ने कहा कि एसपीजी ने मार्ग को मंजूरी दे दी।

ख़ास ख़बरें

चीन में भूस्खलन, 14 लोगों की मौत

बीजिंग : दक्षिण पश्चिमी चीन में एक निर्माणस्थल पर हुए भूस्खलन में 14 लोग मारे गए। गुइझोउ प्रांत के बीजी शहर में हुए इस भूस्खलन का कारण पता करने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्राकृतिक आपदा के साथ मजदूर, अस्पताल के लिए एक प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण कर रहे थे। सारी रात चले बचाव कार्य में एक हजार से ज़्यादा लोग शामिल रहे।

अमेरिका में 60 प्रतिशत से ज़्यादा नए केस

अमेरिका में सामने आने वाले नए मामलों में 60 प्रतिशत से अधिक ओमिक्रॉन के हैं। इसके बाद करीब 38-40 प्रतिशत मामले डेल्टा वेरिएंट के हैं। पिछले दिनों यहां एक ही दिन में 5.90 लाख नए केस सामने आए थे। देश में 29 नवंबर के बाद कोरोना के मामले बेतहाशा बढ़े हैं। 28 नवंबर को जहां कोरोना के नए मामले 23 हज़ार से कुछ ज़्यादा थे वहीं 29 नवंबर को ये एक लाख के पार पहुंच गए।

सिर्फ 03 मामलों पर चीन के युझोऊ शहर में पूर्ण लॉकडाउन

बीजिग : दो सप्ताह के भीतर पूर्व चीन के शियान शहर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन के बाद मात्र 3 मामलों की पुष्टि होने पर 12 लाख की आबादी वाले युझोऊ शहर में पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया। चीन ने शून्य कोविड दृष्टिकोण के तहत यह कार्रवाई की। अधिकारियों ने कहा, इस इलाके को पूरी तरह बंद किया गया, अत: सभी लोगों को सख़्त उपाय अपनाने के निर्देश जारी किए गए। कनाडा का सर्वाधिक आबादी वाले प्रांत ओंटारियों में भी सभी स्कूल बंद कर दिए गए, ब्रिटेन के इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में 1,57,758 नए मामले सामने आए। इटली में 68 हजार नए केस मिले और 140 की मौत की सूचना मिली।

एयरपोर्ट अथॉरिटी व एयर इंडिया की 223 करोड़ की संपत्ति ज़ब्त

कनाडा की एक अदालत के आदेश के बाद इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (आईएटीए) के पास क्यूबेक प्रांत तथा अन्य देशों में मौजूद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया तथा एयर इंडिया की संपत्तियों को ज़ब्त कर देवास मल्टीमीडिया के अंशधारकों को सौंपा जा रहा है। क्यूबेक के सुपीरियर कोर्ट द्वारा इस बारे में पारित दो अलग अलग आदेशों के बाद आईएटीए के पास मौजूद एएआई की 68 लाख डॉलर की संपत्ति ज़ब्त कर ली गई है जबकि देवास के प्रतिनिधियों ने बताया कि कनाडा कोर्ट के आदेश के बाद अब तक एयर इंडिया के 223 करोड़ रुपये की संपत्ति ज़ब्त कर चुके हैं।

अल्लाह तआला को राज़ी करने के लिए कोई चीज़ छोड़ोगे तो वह तुम्हें उसके बदले में इससे बेहतर चीज़ इनायत फरमाएगा (2)

पिछले अंक का शेष....

शेख़ ने उसके चचा को बुलाया, दो गवाह और बुलाए और निकाह कर दिया और तालिब इल्म की ओर से मेहर भी ख़ुद ही अदा कर दिए और इरशाद फरमाया लो अपनी बीवी का हाथ थामो, तालिब इल्म ने उसका हाथ पकड़ा या ख़ातून ने तालिब इल्म का हाथ पकड़ा, और उसको लेकर अपने घर आयी, जब अंदर पहुंची तो अपने चेहरे से नक़ाब हटाया, तालिब इल्म उसका हुस्न व जमाल और शबाब देखकर दंग रह गया, दूसरी आश्चर्य वाली बात यह थी कि यह घर वही था जिसमें वह चोरी करने के लिए आया था, औरत ने पूछा : आप कुछ खाना पसंद करेंगे, तालिब इल्म ने कहा 'हां औरत ने देगची का ढक्कर खोला और जब उसने दांतों के नोचे हुए बैंगन को देखा तो आश्चर्य प्रकट किया इस बात सुनकर तालिब इल्म रोने लगा और उसने अपनी बीवी को पूरा वाक्या सुनाया उसने कहा तुम्हारी दयानत व अमानत का सिला रब्बुल इज्ज़त ने तुम्हें अता किया है, तुमने हराम बेंगन से अपने आपको बचाया तो अल्लाह ने पूरा मकान और उसके हसीन व जमील मकीन को तुम्हारे हवाले कर दिया।

दूसरा वाक्या भी बड़ा अजीब व ग़रीब है वह यह कि एक तालिब इल्म था जिसके अंदर तक़्वा दीनदारी तो थी लेकिन वह मग्फल व मजजूब किस्म का था, जब वह एक शेख़ से इल्म हासिल करके फारिग़ अल तहसील हुआ तो शेख़ ने उसको और उसके साथियों को नसीहत फरमायी कि लोगों के सहारे न रहना किसी पर बोझ मत बनना, क्योंकि आलिम की यह शान नहीं कि वह दुनियादारों के सामने अपने हाथ फैलाए तुम में से हर एक व्यक्ति ख़ुद कफील रहने की कोशिश करके और अपने वालिद के पेशे को रोज़गार बनाएं और इसमें अल्लाह तआला से डरता रहे वह नौजवान अपनी मां के पास गया और पूछा कि मेरे वालिद का क्या पेशा था? उसकी मां ने इधर उधर की बात बनाकर जवाब से बचने की कोशिश की लेकिन वह ज़िद करने लगा और जवाब देने पर मजबूर किया, मां ने मजबूरीवश कहा कि तुम्हारे वालिद चोरी करते थे। तालिब इल्म ने अपनी मां से कहा, 'शेख़ ने मुझे नसीहत की है कि अपने वालिद का पेशा अख़्तयार करो और इसमें अल्लाह का तक़्वा अख़्तियार करो। मां ने कहा तेरा भला हो क्या चोरी में तक़्वा हो सकता है, लड़के ने सादेपन से कहा, 'मेरे उस्ताद ने उसी तरह फरमाया है, आख़िर वह चोरी का पेशा अख़्तियार करने के इरादे से गया, इधर उधर के लोगों से चोरी करने के तरीक़े सीखें और चोरी का सारा साज़ो सामान तैयार किया।

एक दिन ईशा की नमाज़ पढ़कर जब सब लोग सो गए तो अपने वालिद के पेशे का आग़ाज़ करने के इरादे से चला ताकि शेख़ की नसीहत को व्यवहारिक रूप दे, सबसे पहले पड़ौस के घर के दरवाज़े पर पहुंचा तो उसने सोचा कि शेख़ ने तक़्वा के की नसीहत की थी पड़ौसी को तकलीफ देना तो सरासर तक़्वा के ख़िलाफ़ है। आगे बढ़ा तो कुछ यतीमों का घर मिला, दिल में कहा, 'अल्लाह तआला ने कुरआन करीम में यतीमों का माल खाने पर बड़ी वईद सुनायी है इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो उसको एक मालदार व्यापारी का घर नज़र आया जिसके सिर्फ इकलौती बेटी थी और सारे लोग जानते थे कि इसके पास बेशुमार दौलत है जो ज़रूरत से अधिक है, उसने कहा 'यहीं चोरी करना उचित है, वह उस घर में घुस गया और तलाश व जुस्तजू के बाद तिजौरी के करीब जा पहुंचा अपनी चाबियों से सन्दूक का ताला खोला तो बहुत सा सोना चांदी और नक़दी पाया, उसने माल लेने का इरादा किया फिर सोचा नहीं! शेख़ ने तक़्वा की नसीहत की थी मालूम नहीं इस व्यापारी ने अपने माल की ज़कात दी है या नहीं? मुझे पहले ज़कात का माल अलग कर देना चाहिए, फानूस जलाकर कलम कागज़ लेकर हिसाब लगाने बैठ गया, तालिब इल्म हिसाब में बड़ा माहिर था, सारे माल की ज़कात का हिसाब लगाकर फारिग़ हो चुका था उसने कहा 'तकवा का तक़ाज़ा है कि पहले फज्र की नमाज़ अदा की जाए, घर के सहन में आया हौज़ में वजू किया और नमाज़ पढ़ने खड़ा हुआ, आहट सुनकर मकान मालिक की आंख खुल गयी, उसके आश्चर्य की सीमा न रही, तिजौरी का ताला खुला है फानूस जल रहा है, कागज़ात बिखरे पड़े हैं और एक व्यक्ति नमाज़ पढ़ने जा रहा है उसने आकर उससे पूछा कि तुम कौन हो? चोर ने कहा, ' पहले नमाज़ बाद में कलाम, चलो वजू करो और नमाज़ पढ़ाओ क्योंकि नमाज़ की इमामत का हक़ मकान मालिक हो है, मालिक ने सोचा कहीं इसके पास अस्लह (शस्त्र) न हो उसने मारे डर के उसकी बात मान ली और जैसे तैसे नमाज़ पढ़ी इसके बाद उसने कहा 'अब बताईये, आप कौन हैं, उसने कहा 'मैं चोर हूं मालिक बोला आप कलम कागज़ लेकर क्या कर रहे थे? चोर ने जवाब दिया 'आप ने छह वर्ष की ज़कात अदा नहीं की थी, मैंने उसका हिसाब लगाया है, अब जक़ात की रक़म अलग रख दी है ताकि आप उसको उसके उचित पात्र को दे दें, मालिक आश्चर्य में डूब गया और करीब था कि पागल हो जाए, फिर उसने चोर से पूछा, आप अपने पूरे मामले की हक़ीक़त मुझे बताईये, आप मजनू तो नहीं हैं? उसने अपना पूरा वाक्या उस व्यापारी को सुनाया, व्यापानी ने जब कागज़ात देखें तो उसके हिसाब के इल्म से बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, जब उसने उसकी खूबसूरती देखी और उस का पूरा वाक्या सुना तो उसकी शराफ़त और उसके भोलेपन से और पूरे वाक्ये से बड़ा प्रभावित हुआ, उसने अपनी बीवी से मशवरा किया और फिर उस व्यक्ति से कहा कि आपकी क्या राय है? मैं अपनी बेटी का निकाह आप से करना चाहता हूं और आपको अपना मुंशी और सलाहकार बनाता हूं, तुम अपनी वालिदा के साथ मेरे उस घर में रहना, वह इस पर राज़ी हो गया, सुबह हुई, गवाहों को और लोगों को बुलाया गया और निकाह करा दिया गया। ❑❑

कमज़ोर इश्क़

मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह एक दिन ख़रीद व फरोख़्त के सिलसिले में बाज़ार तशरीफ़ ले गए, एक दुकान पर जाकर रुक गए। देखा कि एक औरत कुछ सौदा सलफ़ ले रही है। सौदा खरीदने के बाद उस औरत ने अब रक़म अदा करनी चाही तो दुकानदार ने कहा 'इश्क़ में हिसाब किताब कहां होता है, छोड़ो पैसे और जाओ।' अस्ल में यह दोनों आशिक़ और माशूक़ थे। मौलानाा रूमी रहमतुल्लाह अलैह यह सुनकर ग़श खाकर गिर पड़े। दुकानदार सख़्त घबरा गया। इस दौरान में वह औरत वहां से चली गई। ख़ासी देर बाद जब मौलाना रूमी रहमतुल्लाह को होश आया तो दुकानदार ने पूछा ''मौलाना साहब! आप क्यों बेहोश हुए।''?

मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैहे ने जवाब दिया ''मैं इस बात पर बेहोश हुआ कि तुम दोनों में इतना क़वी और मज़बूत इश्क़ है कि आपस में कोई हिसाब किताब नहीं जबकि अल्लाह के साथ मेरा इश्क़ इतना कमज़ोर है कि मैं तस्बीह के दाने गिन-गिन कर गिराता हूँ।''

नूरे क़ुरआन

(सूरा अल क़द्र नं॰ 97)

अनुवाद और व्याख्या : शैख़ुल हिन्द र.अ.

सो आप अपने पालनहार के आगे नमाज़ पढ़िये और कुर्बानी कीजिए।

अर्थात् इतने बड़े ईनआम और उपकार के लिए धन्यवाद भी बड़ा होना चाहिए कि आप अपनी आत्मा, शरीर और माल (तन, मन और ध न) से बराबर अपने रब की उपासना में लगे रहें। शारीरिक और आत्मिक उपासना में सबसे बड़ी चीज़ नमाज़ और माली इबादत में कुर्बानी विशेष स्थान रखती है क्योंकि कुर्बानी की वास्तविकता अपनी जान कुर्बान करना था। जानवरों की कुर्बानी कुछ विशेष तात्विकताओं के आधार पर उसके स्थान पर रख दी गयी, जैसे हज़रत इब्राहीम व इस्माईल अलै॰ क़िस्से से सूरा नं॰ 37 रुकू नं॰ 3 में विदित होता है इसलिए कुरआन में दूसरे स्थानों पर भी नमाज़ और कुर्बानी का वर्णन साथ-साथ किया है।

चेतावनी :- मुश्ररिकीन कुर्बानी और नमाज़ बुतों के लिए करते थे, मुसलमानों को यह काम केवल अल्लाह के लिए करना चाहिए।

रुकू नं॰ 1

निःसंदेह आपका शत्रु ही बेनामों निशान है।

कुछ इनकारी हज़रत मुहम्मद सल्ल॰ के संबंध में कहते थे कि इस व्यक्ति के यहां कोई बेटा नहीं, बस जीवन भर तक इसका नाम है पीछे कौन नाम लेगा। ऐसे व्यक्ति को उनकी बोल-चाल में अबतर (उत्ता) कहते थे, अबतर वास्तव में दुम कटे जानवर को कहते हैं। जिसके पीछे कोई नाम लेवा न रहे जैसे उसकी पूंछ कट गई। कुरआन ने बतलाया कि जिसको अल्लाह अधिक से अधिक अच्छाईयां दे और अनन्त काल तक नाम रोशन करे, उसको अबतर कहना बड़ी मुर्खता है। वास्तव में अबतर वह है जो महान प्रिय हस्ती से ईर्ष्या और शत्रुता रखे और अपने पीछे कोई अच्छाई का वर्णन और नेक कामों का प्रभाव न छोड़े। आज चौदह सौ वर्ष बीत जाने पर अल्लाह का शुक्र है हुज़ूर की आत्मिक औलाद से दुनिया भरी पड़ी है और शारीरिक बेटी की औलाद भी अधिक मात्रा में, विदेशों में फैली पड़ी है। आपके दीन और नेक काम और अच्छी शिक्षा के नमूने संसार में चमक रहे है। आपकी याद, नेकनामी, मुहब्बत और श्रद्धा के साथ करोड़ों इंसानों के दिलों में गर्मी दे रही हैं। दोस्त दुश्मन सब आपके सुधार के कामों को सच्चे दिल से स्वीकार करते हैं। फिर दुनिया से चले जाने के पश्चात् आख़िरत में आप जिस महमूद नामक स्थान पर खड़े होंगे और जो सम्मान व लोकप्रियता आपको प्राप्त होगी, वह अलग रही। क्या ऐसी अमर हस्ती को अबतर कहा जा सकता है। इसके मुक़ाबले में उस मूर्ख का विचार करो, जिसने वह वाक्य मुंह से निकाला था उसका नामों निशान कहीं बाक़ी नहीं न आज भलाई के साथ उसे कोई याद करने वाला है। यही हाल उन तमाम धृष्ट लोगों का है, जिन्होंने किसी समय आपकी दुश्मनी में कमर बांधी थी और आपके सम्मान को ठेस पहुंचाई थी इसी प्रकार आगे होता रहेगा।

(सूरा अलकाफीरून नं॰ 109)

यह सूरा मक्का में उतरी इसमें 06 आयतें हैं।

प्रारंभ करता हूं मैं अल्लाह के नाम से जो असीम कृपालु महादयालु है।

आप कह दीजिए ऐ सच्चे दीन का इनकार करने वालो।

कुछ अमीर धनवान कुरैश ने कहा - ऐ मुहम्मद आओ हम तुम मेल कर लें कि साल तक आप हमारे उपास्यों की उपासना किया करें। फिर दूसरे साल हम आपके उपास्य की उपासना करेंगे। इस प्रकार दोनों वर्गों को प्रत्येक के दीन से थोड़ा थोड़ा भाग मिल जायेगा। आपने कहा - अल्लाह की पनाह (अल्लाह हमें सुरक्षा में रखे) कि मैं अल्लाह के साथ एक क्षण के लिए भी किसी को साझी ठहराऊँ। फिर कहने लगे कि अच्छा तुम हमारे कुछ उपासयों को मान लो, उनकी बुराई न करो। हम आपको मान्यता देंगे और तुम्हारे अल्लाह की उपासना करेंगे। इस पर यह सूरा उतरी और आपने उनके समूह में पढ़कर सुनाई जिसका सारांश मुश्रिकों की कार्यवाही से बिल्कुल अलगाव का ऐलान करता है। भला रसूल जिसका पहला काम शिर्क (अल्लाह का साझी बनाना) की जड़ें काटना है।

आख़िर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में क्या होने वाला है?

उत्तर प्रदेश में किस पार्टी को मिलेगा जनता का कितना समर्थन? उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, तमाम लोग अपनी- अपनी तरह से चुनावों के गणित को समझाने और सुलझाने में जुटे हैं। हर चौक चौबारे पर, हर चाय के अड्डे पर, हर नाई की दुकान पर और हर मध ुशाला में यही चर्चा हो रही है कि इस बार उ.प्र. में क्या होने वाला है?

इस प्रश्न का उत्तर तो बड़े-बड़े दिग्गज भी तलाश रहे हैं। तमाम कंपनियां सर्वे करा रही हैं, राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी और बड़े राजनीतिक विश्लेषक भी इसी प्रश्न का हर निकालने में जुटे हैं। पुराने डेटा को खंगाला जा रहा है, जातिगत समीकरण और सोशल इंजीनियरिंग के पैमानों पर चीज़ों को कसा जा रहा है। मुख्यधारा के मीडया वाले और तमाम तरह के सोशल मीडिया वाले पत्रकार भी यूपी की यात्राओं पर निकले हुए हैं, लेकिन क्या यूपी की जनता का दिल टटोलना वाक़ई इतना ही आसान है?

तमाम लोग समझना चाहते हैं कि जब अखिलेश सक्रिय हैं तो मायावती कहां हैं, प्रियंका सक्रिय हैं तो मायावती कहां हैं? वो कौन सी तैयारी कर रही हैं? सभी इस बात को जानते है। कि मायावती को कम करके आंका नहीं जा सकता। वो ऐसी नेता है जिनके पास वोटबैंक भी है और अनुभव भी है लेकिन उनका बाकी नेताओं की तरह ना दिखना उनके चाहने वालों को खलता भी है। विशेषकर दलित युवा वर्ग को, जो सोशल मीडिया को देखकर अपनी राय बनाता है। घर के बड़े तो हाथी पर बटन दबा देंगें लेकिन क्या वे युवा लोग बसपा पर भरोसा करेंगे? वो भी तब, जब भीम आर्मी के लोग सोशल मीडिया के ज़रिए ऐसे युवाओं का दिल जीतने में जुटे हैं। भाजपा भी इसी युवा वर्ग को अपने पक्ष में करना चाहती है। वहीं मायावती और उनकी पार्टी सोशल मीडिया पर अभी भी काफी पीछे हैं। दूसरी ओर पार्टी का लगातार ब्राह्मण सम्मेलन करना और सर्वजन की बातें करना भी काफी लोगों को रास नहीं आ रहा है। व्हाटऐप पर भड़काऊ मैसेज देखने वाले ऐसे हज़ारों लाखों लोग हैं जो ख़ुद भी सोशल मीडिया पर आक्रामक हैं और मायावती से भी आक्रामक होने की उम्मीद रखते हैं लेकिन मायावती का रवैया उनकी समझ में नहीं आ रहा है। मायावती ख़ुद भी इस बात को समझती होंगी कि ये चुनाव उनके लिए है अहम है क्योंकि वे अभी करीब 65 वर्ष की हैं और बार-बार उत्तराधिकारी को लेकर प्रश्न उठते हैं।

एक प्रश्न यह भी है कि क्या अखिलेश यादव की सभाओं वाली भीड़ वोटों में तब्दील होगी? अखिलेश की सभाओं में पिछले दिनों जितनी भी सभाएं की उसमें भीड़ उमड़ी दिखी। अखिलेश ने चौधरी जयंत सिंह से हाथ मिला लिया है, चाचा शिवपाल को भी गले लगा लिया है और तो और ख़ुद पीएम भी 'लाल टोपी' का ज़िक्र कर चुके हैं। यानि विरोधी भी उन्हें गंभीरता से ले रहे हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या ये भीड़ वोटों में तब्दील होगी? क्या अखिलेश जनता को अपनी बात समझा पाएंगे और क्या जनता इस बार अखिलेश को मौक़ा देगी? 2012 में अखिलेश बेशक सीएम थे, लेकिन उनकी पार्टी के अन्य बड़े नेता भी उनकी कार्यप्रणाली पर अक्सर हावी नज़र आते थे। बाद में हालात बिगड़ और बहुत बिगड़े। पार्टी दो फाड़ हो गई। अखिलेश राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, मुलायम मार्गदर्शक की स्थिति में आ गए। मंच पर हुए बवाल को पूरे देश ने देखा। 2017 में वो जीत नहीं पाए, 2019 के लोकसभा चुनाव में भी प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। अखिलेश की सरकार के दौरान लिए गए फैसलों पर भाजपा ने काफी प्रश्न भी किए। इसके बाद भी अखिलेश डटे रहे, जमे रहे और भाजपा से पूरा दम-खम लगाकर भिड़े रहे। इसका फायदा तो मिलेगा। भाजपा के खिलाफ़ जो जनता है वो अखिलेश में अवसर देख रही है लेकिन इसके बाद भी उन्हें जीत के लिए बहुत संघर्ष करना होगा। बयानों के तीरों को थोड़ा और समझकर चलाना होगा। माया की तरह अखिलेश के पास आयु की तो फिलहाल कोई दिक्क़त नहीं है लेकिन अगर इस बार वे जीत नहीं पाए तो उनके नेतृत्व और गठबंधन के फैसलों पर तमाम प्रश्न खड़े हो सकते हैं।

एक प्रश्न यह भी है कि क्या प्रियंका गांधी बना सकेंगी कांग्रेस को तीसरे नंबर की पार्टी? कांग्रेस के नेता भले ही लाख जीत के दावे करें लेकिन वो जानते हैं कि उनकी पार्टी सरकार बना नहीं सकती। संगठन कमज़ोर है और स्टार नेताओं की भी कमी है। भाजपा ने पिछले 10 सालों में जिस पार्टी को सबसे अधिक नुकसान दिया है, वो कांग्रेस ही है। बात यूपी की करें तो कांग्रेस का प्रदर्शन पिछले विधानसभा चुनावों से लेकर लोकसभा चुनावों तक में अच्छा नहीं रहा है। लेकिन जिस तरह से फिलहाल पार्टी काम कर रही है, जिस तरह से मुद्दों को लपक रही है,

बाक़ी पेज 11 पर

कैप्टन अमरेन्द्र 64वें नेता जिन्होंने कांग्रेस से अलग होकर नई पार्टी बनाई

पंजाब में कांग्रेस छोड़ने के बाद आख़िरकार कैप्टन अमरेंद्र सिंह ने नई पार्टी का ऐलान कर ही दिया। उन्होंने पंजाब लोक कांग्रेस नाम से नई पार्टी का गठन किया है। यह भी कहा कि वह पंजाब में अगला चुनाव भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर लड़ेंगे। इसी के साथ यह 64वीं बार है जब कांग्रेस से अलग होकर कोई नेता पार्टी खड़ी कर रहा है। 1885 से अब तक कांग्रेस ने 64 ऐसे अवसर देखे जब कांग्रेस छोड़ने के बाद नेताओं ने अपनी नई पार्टी बना ली। 1969 में तो कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने इंदिरा गांधी को ही पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। तब इंदिरा ने अलग होकर कांग्रेस बना ली थी। सोनिया गांधी के अध्यक्ष रहते सबसे ज़्यादा फूट पड़ी। 1998 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी की कमान संभाली थी। तब से लेकर अब तक कांग्रेस की फूट से 26 नए दल बन चुके हैं।

1923 : चितरंजन दास ने कांग्रेस छोड़कर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। होम लाइब्रेरी की पुस्तक 'ग्रेट मेन ऑफ इंडिया' में उसका उल्लेख किया गया है। बताया गया है कि चितरंजन दास काउंसिल में शामिल होकर ब्रिटिश सरकार की नीतियों का नए तरह से विरोध करना चाहते थे लेकिन कांग्रेस अधिवेशन में उनका यह प्रस्ताव पास नहीं हो सका। इसके बाद उन्होंने स्वराज पार्टी बना ली। 1924 में दिल्ली में कांग्रेस के अतिरिक्त अधिवेशन में उनका यह प्रस्ताव पास हो गया। 1925 में स्वराज पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया।

1939 : महात्मा गांधी से अनबन होने पर सुभाष चन्द्र बोस और शार्दुल सिंह ने ऑल इंडिया फारवर्ड ब्लाक नाम से अलग पार्टी खड़ी कर ली। पश्चिम बंगाल में अभी भी यह पार्टी अस्तित्व में है हालांकि इसका जनाध ार काफी कम हो चुका है।

आज़ादी के बाद कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं ने 1951 में तीन नई पार्टियाँ खड़ी कीं। इसमें जीवटराम कृपलानी ने किसान मज़दूर प्रजा पार्टी, तंगुतूरी प्रकाशम और एन.जी. रंगा ने हैदराबाद स्टेट प्रजा पार्टी और नरसिंह भाई ने सौराष्ट्र खेदूर संघ नाम से अलग राजनीतिक पार्टी बनाई थी। इसमें हैदराबाद स्टेट प्रजा पार्टी का विलय किसान मज़दूर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और सौराष्ट्र खेदूर संघ का विलय स्वतंत्र पार्टी में हो गया।

कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे सी. राजगोपालाचारी ने 1956 में पार्टी छोड़ दी। बताया जाता है तमिलनाडू में कांग्रेस नेतृत्व से विवाद होने के बाद उन्होंने अलग होने का फैसला लिया था। राजगोपालाचारी ने पार्टी छोड़ने के बाद इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक्स कांग्रेस पार्टी की स्थापना की। यह पार्टी मद्रास तक ही सीमित रही। हालांकि बाद में राजगोपालाचारी ने एन.जी. रंगा के साथ 1959 में स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की ली और इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक्स पार्टी का इसमें विलय कर दिया। स्वतंत्र पार्टी का फोकस बिहार, राजस्थान, गुजरात, ओडिशा और मद्रस में अधिक था।

1974 में स्वतंत्र पार्टी का विलय भी भारतीय क्रांति दल में हो गया था। इसके अलावा 1964 में के.एम. जार्ज ने केरल कांग्रेस के नाम से नई पार्टी का गठन कर लिया। हालांकि बाद में पार्टी से निकले नेताओं ने अपनी सात अलग अलग पार्टियां खड़ी कर लीं। 1966 में कांग्रेस छोड़ने वाले हरेकृष्णा मेहताब ने ओडिशा जन कांग्रेस की स्थापना की। बाद में इसका विलय जनता पार्टी में हो गया।

यह बात 12 नवंबर 1969 की है। तब कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को ही पार्टी से निकाल दिया। उन पर अनुशासन भंग करने का आरोप लगाया गया था। इसके जवाब में इंदिरा गांध ी ने नई कांग्रेस खड़ी कर दी। इसे कांग्रेस आर0 नाम दिया गया। बताया जाता है कि जिन नेताओं ने इंदिरा को पार्टी से निकाला था उन्हीं ने 1966 में उन्हें प्रधानमंत्री बनाया था। तब इंदिरा गांधी के पास अनुभव और संगठन की समझ कम थी। हालांकि, सरकार चलाने के साथ ही वह एक मज़बूत राजनीतिज्ञ के रूप में भी उभरकर कर देश के सामने आई। 1967 में उन्होंने अपने अकेले दंम पर चुनाव लड़ा और मज़बूती से जीत हासिल की।

इंदिरा से विवाद के चलते ही के. कामराज और मोरारजी देसाई ने इंडियन नेशनल कांग्रेस आर्गेनाइजेशन नाम से अलग पार्टी बनाई थी। बाद में इसका विलय जनता पार्टी में हो गया। 1969 में ही बीजू पटनायक ने ओडिशा में उत्कल कांग्रेस, आंध्र प्रदेश में एम. चेना रेड्डी ने तेलंगाना प्रजा समिति का गठन कियास। इसी तरह 1978 में इन्दिरा ने कांग्रेस आर. छोड़कर एक नई पार्टी का गठन किया इसे कांग्रेस (आई) नाम दिया। एक वर्ष बाद यानि 1979 में डी. देवराज अर्स ने इंडियन नेशनल कांग्रेस अर्स नाम से पार्टी का गठन किया। देवराज की पार्टी अब अस्तित्व में नहीं रही। 1998 में ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी बना ली। वह पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री हैं इसके एक वर्ष बाद ही शरद पवार, पी.ए. संगमा और तारिक अनवर ने नैशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का गठन कर लिया था। अब इसे एन.सी.पी. के नाम से जाना जाता है। शरद पवार अभी भी इसके प्रमुख हैं आख़िरी बार 2016 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के बड़े नेता रहे अजीत जोगी ने पार्टी छोड़कर छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस नाम से नया दल बना लिया। 1885 को अस्तित्व में इंडियन नेशनल कांग्रेस के इतने लम्बे इतिहास में पंजाब के कैप्टन अमरेन्द्र सिंह 64वें ऐसे नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस से अलग होकर नई पार्टी बनाई है। ❑❑

मुझे किसी ने नहीं बताया था टीम इंडिया से क्यों निकाला हरभजन

वर्ष 2021 का आख़िरी सप्ताह आखिरकार एक और महान खिलाड़ी के संन्यास का काल बनकर गया। दिग्गज भारतीय ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी। घरेलू क्रिकेट में पंजाब के लिए खेलने वाले हरभजन ने 1998 बंगलुरु में आस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ टेस्ट मैंच के साथ अंतर्राष्ट्रीय पर्दापण किया था। उन्होंने मार्च 2001 में आस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ तीन टैस्ट मैचों की सीरीज में 32 विकेट लिए थे। इस दौरान वह हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज़ बने थे। उन्होंने मार्च 2016 में ढाका में संयुक्त अरब अमीरात के ख़िलाफ़ टी-20 मैच के रूप में अपना अन्तिम मैच खेला। उसके बाद वह लगातार आईपीएल खेले, लेकिन टीम इंडिया में उनकी वापसी नहीं हो सकी। उन्हें इस बात का गिला है कि उन्हें टीम से बाहर करने का कारण कभी नहीं बताया गया और इस बात का मलाल है कि उन्हें मैदान में खेलते हुए क्रिकेट से विदा लेने का अवसर नहीं दिया गया। पेश हरभजन सिंह हुई एक विस्तृत बातचीत के प्रमुख अंश :-

सवाल:- संन्यास लेने में इतनी देर कने की क्या वजह रही है?

जवाब:- कई सालों से दिमाग़ में चल रहा था। पता नहीं चला समय कैसे निकल गया, लेकिन अब ले लिया है।

सवाल:- आप फिल्में भी करते हैं और आपके लिए राजनीति में आने और किसी आईपीएल टीम में कोचिंग करने की बात भी चलती रहती है, तो आपकी आगे की क्या योजना है?

जवाब:- ऐसी कुछ आगे की योजना तो मैंने अभी तय नहीं की है, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। जो यहां तक लेकर आया है वह आगे भी ज़रूर रास्ता दिखाएगा। बंदा करना चाहे तो करने के लिए तो बहुत से काम है, पर मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूं कि क्रिकेट में इतना सब कुछ कर पाया। आगे भी क्रिकेट से जुड़ा रहना चाहूंगा, फिर चाहे वो किसी भी तरह का हो, चाहे कोचिंग के रूप में हो या मेंटर के रूप में हो। जिस क्रिकेट की वजह से आज मैं हूं, तो मैं चाहूंगा कि क्रिकेट को अगर मैं कुछ वापस दे सकूं तो ज़रूर युवा खिलाड़ियों को कुछ सिखाकर देने की कोशिश करूंगा।

सवाल:- हाल में भारत के कई बड़े-बड़े क्रिकेटरों ने मैदान में खेलकर संन्यास लेने की जगह इस तरह से संन्यास लिया, क्या और बेहतर नहीं होता कि आप मैदान से संन्यास लेते या आपका अपना निर्णय था कि मैं ऐसे ही आईपीएल खेलूंगा और जब मुझे संन्यास लेना होगा, लूंगा?

जवाब:- हाँ, निर्णय तो मेरा ही था कि मुझे संन्यास कब लेना है और कब नहीं। चाहता तो हर क्रिकेटर की तरह मैं भी था कि मैदान से संन्यास ले लेता तो अच्छा होता, पर ऐसा नहीं हो पाया। कहते हैं न कि आपको ज़िन्दगी में हर चीज़ नहीं मिलती है, चाहे कितनी भी कोशिश करते रहो।

सवाल:- आपको कुंबले के बाद नंबर दो गेंदबाज़ रहने का मलाल तो रहेगा ही?

जवाब:- मुझे ऐसा कोई मलाल नहीं है कि मैं नंबर दो पर रहूं या 10 पर रह गया। ये नंबर सिर्फ आपके ज़ेहन में है। मुझे सिर्फ इस बात की ख़ुशी है कि मैं इतने वर्ष भारतीय टीम में खेल सका और योगदान कर सका। अफसोस जताने के लिए कहते रहेंगे कि यह ठीक नहीं हुआ, वह ठीक नहीं हुआ। मैं खुशकिस्मत हूं कि मुझे रब ने इस लायक़ बनाया कि मैं इतने लंबे समय तक खेल सका। 100 टैस्ट मैच खेलना बहुत बड़ी बात होती है। मेरा उद्देश्य था कि मैं 100 टैस्ट खेलने वाला भारतीय गेंदबाज़ बनूं, तो वो बना भी। कई चीज़ें रह जाती हैं, जो आप नहीं कर पाते हो, मगर ज़िन्दगी सिर्फ क्रिकेट नहीं इससे आगे बहुत कुछ और करना है।

सवाल:- लेकिन आपने एक एक शो में श्रीकांत आए हुए थे तो आपने कहा था कि जब मैं अच्छा प्रदर्शन कर रहा था तो अपने निकाल दिया था?

जवाब:- बिल्कुल कोई 400 विकेट खराब गेंदबाज़ी करके तो मिलते नहीं हैं। जब कोई 400 विकेट लेता है तो उसके बाद उसको खेलने का मौक़ा ही नहीं मिले या उसको बताया ही नहीं जाए कि उसको क्यों बाहर किया गया, तो बहुत बड़े प्रश्न उठते हैं ज़ेहन में। जिसका किसी ने जवाब नहीं दिया। मैंने कई लोगों से जानने की कोशिश की, चयनकर्ताओं से लेकर मैंने हर किसी से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन तब किसी ने मुझे नहीं बताया कि मुझे क्यों बाहर किया गया। अब 400 विकेट लेने वाला बंदा चयनकर्ताओं के आगे जाकर तो यह नहीं पूछेगा कि मुझे क्यों नहीं चुना जा रहा, मुझे मुझे जवाब तो दो मुझे क्यों नहीं चुना जा रहा है। क्या अचानक से मेरी शक्ल खराब हो गई है या मेरी गेंदबाज़ी इतनी खराब हो गई है। यह भारतीय क्रिकेट की एक दुखद कहानी हे, जहां पर जिसने कुछ हासिल किया है, यदि उसकी ज़रूरत नहीं लगी तो फिर बाद में किसी ने उससे ठीक से बात भी नहीं की।

सवाल:- उसके बाद भी सालों बीत गए तो जवाब मला कि नहीं?

जवाब:- जवाब जिनसे मिलने थे उनसे हमने दोबारा पूछने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि बीता हुआ समय वापस आएगा ही नहीं अब जब वे लोग जो उस पोजीशन में थे वे अब यही कहकर मिलते हैं कि सारी, हमने तब गलती की थी। किसी ने बताया कि हमारे ऊपर दबाव था, हम ऐसा कर नहीं पाए। ठीक है, जब आप कर सकते थे तो तब आपने क्यों नहीं किया, तो अब उस सॉरी का क्या फायदा। सॉरी से ज़िन्दगी तो नहीं बदलने वाली है। 2011-12 के बाद मेरे लिए चीजें अलग हो गई हालांकि, मैं आईपीएल में लगातार प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन मुझे टीम इंडिया में ही नहीं लिया गया और जब लिया गया तो खिलाया ही नहीं गया। मैं नहीं जानता कि उसके क्या कारण रहे, मगर ठीक है, जो हुआ अच्छा ही हुआ।

सवाल:- अभी अश्विन ने भी कहा था कि उनके जीवन में एक समय आया था जब उन्हें लगा था कि उन्हें संन्यास ले लेना चाहिए या उन्हें उस तरह का सपोर्ट नहीं मिल रहा था, तो कभी आपको भी लगा कि अब बस बहुत हो गया..?

जवाब:- सपोर्ट जब तक मिलती है तब तक तो बहुत अच्छा लगता है। मैं तो यही कहूंगा कि सपोर्ट ठीक समय पर मिलती तो शायद यह संन्यास मैं 500-550 विकेट लेकर बहुत पहले ले लेता, क्यों जब मैं मात्र 31 वर्ष का था तो मैंने 400 विकेट लिए थे और अगर तीन-चार वर्ष और खेलता तो 500-550 विकेट तो ले ही लेता। लेकिन वो सब हुआ नहीं।

सवाल:- गांगुली ने आपको काफी सपोर्ट दिया, जिससे आप आगे बढ़े, लेकिन अभी जो बीसीसीआई में चल रहा है उसे लेकर गांगुली पर ही प्रश्न उठाए जा रहे थे, आप गांगुली को बतौर कप्तान व बीसीसीआई अध्यक्ष कैसे देखते हैं.?

जवाब:- मेरा तो यह संन्यास वाला दिन है, जितना मैं गांगुली को जानता हूमं वह बहुत साफ इंसान

बाक़ी पेज 11 पर

'जेस' करेगा टेढ़े पँजे ठीक

पैर के पँजों का टेढ़ा होना एक विकृति है, जो भारत में काफी संख्या में देखी जाती हैं अनुमानत: प्रति एक हजार जीवित जन्मे बच्चों में एक से लेकर चार बच्चे इस प्रकार की एक जन्मजात विकृति का शिकार होते हैं। पैर के पंजे टेढ़े होने को 'क्लब फुट' कहते हैं। यह एक जन्मजात विकृति है, जिसमें एक या दोनों पैरों के पंजे टेढ़े हो जाते हैं। पैर में कई छोटी-छोटी हड्डियां होती हैं, जो आपस में जोड़ों का निर्माण करती है। सामान्य बच्चों में यह जोड़ भी सामान्य चाल और गति देते है, लेकिन क्लब फुट के साथ जन्मे बच्चों में ऐसा नहीं होता।

क्या है उपचार!

टेढ़े पँजों के साथ पैदा बच्चों का इलाज प्रसव के तुरंत बाद शुरू कर देना चाहिए। तीन सप्ताह के भीतर यदि इलाज शुरू कर दें, तो सबसे अच्छा हैं। इस समय को गोल्डन पीरियड कहते हैं, क्योंकि मां के गर्भ से हार्मोन बच्चे के रक्त में जाता है, जो तीन सप्ताह तक रहता है। इस अवधि में मांसपेशियां ज़्यादा लचीली रहती हैं और ठीक होने की संभावना भी अधिक होती है। छह से आठ प्लास्टर लगाने के बाद टेढ़े पंजे ठीक हो जाते हैं। अगर बीमारी पुन: होती है, तो उपचार प्लास्टर नहीं, बल्कि सर्जरी है। परंपरागत सर्जरी में चीरा लगाकर मांसपेशियों को काटकर पैर को सही स्थिति में रखकर मांसपेशियों को सिल दिया जाता है। आजकल टेढ़े पंजों के लिए परंपरागत सर्जरी के स्थान पर अत्याधुनिक विधि यानि जेस तकनीक ज़्यादा प्रचलित है। इस विधि में हड्डी में तार डालकर उनके ऊपर एक शिकंजा कस देते हैं। इस शिकंजे में कुछ चूड़ियां होती हैं, जिनको नियमित रूप से कसना होता है। इसके चलते विकृति ठीक हो जाती हैं पंजे की लंबाई बढ़ती है, जो परंपरागत सर्जरी से नहीं बढ़ती है। इस ऑपरेशन के लिए अस्पताल में एक या दो दिन ही रुकना पड़ता हैं इस तकनीक की सबसे ख़ास बात यह है कि विकृति दोबारा होने की आशंका बहुत कम होती है। यह तकनीक उन लोगों के लिए उत्तम है, जिनका इलाज नहीं हुआ हो। इलाज छोटी उम्र में ऑपरेशन या प्लास्टर द्वारा हुआ हो, लेकिन पंजे फिर से टेढ़े हो गए हों। वह पंजे जिनमें प्लास्टर की विधि से फायदा नहीं हुआ हो।

त्वचा को बीमार होने ही क्यों दें

शहरी वातावरण में प्रदूषण खतरनाक स्तर तक बढ़ रहा है, जो त्वचा की समस्याओं का सबसे बड़ा कारण है। इसके अलावा तनाव भी इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अध्ययनों में यह बात सामने आई है कि तनाव के कारण त्वचा का सुरक्षा कवच के रूप में जो कार्य है, वह प्रभावित होता है। इसके कारण त्वचा एलर्जिक प्रतिक्रिया देती है, जिसकी वजह से त्वचा पर एटॉपिक डर्मेटाइटिस जैसी समस्याएं पैदा होती हैं।

एटॉफिक डर्मेटाइटिस एक प्रकार का एग्जिमा है, जिसके कारण त्वचा लाल और खुजली वाली हो जाती हे। यह बच्चों में एक सामान्य समस्या है, लेकिन यह किसी भी उम्र में हो सकती है। कभी-कभी यह अपने साथ अस्थमा या फीवर की समस्या भी लेकर साथ आती है इसका कोई उपचार तो नहीं है, लेकिन उपचार और थोड़ी देखभाल से खुजली और इसके दूसरे लक्षणों को नियंत्रण में रखा जा सकता है। एटॉफिक डर्मेटाइटिस से आंखों की समस्या जैसे पलकों पर खुजली होना तथा आंखों से पानी आना, त्वचा का संक्रमण जैसी जटिलताएं भी हो सकती हैं।

शेष.... प्रथम पृष्ठ

की ज़मीन तैयार हो जाएगी। ऐसी खास प्रवृत्ति पर चुप्पी आगे किस तरह हिंसा का हंगामा तैयार करती है इसके उदाहरण भरे पड़े हैं।

बहुमत जब बेअदब हो जाता है तो वो सबसे पहले चोट जनतंत्र को पहुंचाता है। यह कौन तय करेगा कि पंजाब में जो व्यक्ति मारा गया उसने क्या अपराध किया? ज़ाहिर है किसी भीड़ को तो नहीं करना है। लेकिन उत्तर प्रदेश से लेकर झारखंड और पंजाब तक यह प्रवृत्ति फैल रही है। नागरिकों को क़ानून और संविधान की बेअदबी करने वाली भीड़ बना दिया जा रहा है। यह अगर हर जगह इसी तरह तय होने लगे तो हम फिर वहीं पहुंच जाएंगे जहां से आगे बढ़ने के लिए नानक और कबीर जैसे गुरुओं ने अपने उदार ज्ञान की अंगुली पकड़ाई थी।

जहां तक हरिद्वार में कथित धर्म संसद और उसमें नफ़रतअंगेज़ भाषणों का प्रश्न है यह सब अल्पसंख्यकों के विरुद्ध एक योजनाबद्ध षड्यंत्र है जिसे बदकिस्मती से सरकार का मूक संरक्षण प्राप्त है। अगर ऐसा न होता तो कोई वजह नहीं थी कि इस कथित धर्म संसद को आयोजित करने वाले और उसमें अल्पसंख्यकों को विशेषकर मुसलमानों के विरुद्ध भड़काऊ और हिन्दुओं को उनके क़त्ल कर देने और भारत को म्यांमार बनाने की धमकियां परोसने वाले आज जेल की सलाखों के पीछे न होते फिर भी यह बात हर अवस्था में प्रसन्नतायोग्य है कि अभी देश में लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्ष के चाहने वाले बड़ी संख्या में मौजूद हैं। जो इस धर्म संसद के आयोजन और इसमें की जाने वाली घृणास्पद वार्ताओं की खुलकर निन्दा कर रहे हैं। अभी हाल ही में बीते वर्ष 26 दिसंबर को उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश 75 सीनियर वकीलों ने चीफ जस्टिस रमन्ना को एक पत्र लिखकर उनसे अनुरोध किया कि वह हरीद्वार की धर्म संसद में की गयी भड़काऊ स्पीच का स्वयं नोटिस लेकर अल्पसंख्यकों और उनके अधिकारों की सुरक्षा को यकीनी बनाएं।

पत्र में सभी आरोपियों का नाम लिखते हुए वकीलों ने कहा है कि यह केवल भड़काऊ भाषण का मामला नहीं है बल्कि यह एक पूरी कम्युनिटी को क़त्लेआम की खुली बात है। इसमें लिखा गया है कि इसमें न केवल देश की एकता और अखंडता को भारी ख़तरा है बल्कि लाखों मुसलमानों की ज़िन्दगियां ख़तरे में आ गयी हैं। मुख्य न्यायाधीश से मांग की गई कि हालात की गंभीरता को देखते हुए वह मामले में स्वत:संज्ञान लेते हुए अपराधियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी 121ए, 153ए 153बी, 295ए, 298 और 1860 के अनुसार कार्रवाई का आदेश जारी करें। इसमें यह भी कहा गया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 153, 153ए, 153बी, 295ए, 504, 506 120बी, और 34 के अनुसार अभी तक भड़काऊ भाषणों के बारे में कोई गंभीर कार्रवाई नहीं की गयी है इसलिए इस मामले में न्यायिक हस्तक्षेप की सख़्त आवश्यकता है।

इससे पहले स्वयं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने विजयवाड़ा के एक प्रोग्राम में भाषण देते हुए यह माना था कि लोकतंत्र में क़ानून के हुक्मरानी की भारी अहमियत है उन्होंने साफ कहा कि अगर किसी देश में क़ानून का शासन नहीं है, वहां फिर अव्यवस्था का ही राज हो सकता है। उन्होंने कानूनसाज़ों और वकीलों को मश्वरा दिया कि वह इस बारे में एक राय बनाए और और जनता को उनके अधिकारों से अवगत कराएं।

हमारे सोच के अनुसार क़ानून विशेषज्ञों की यह कोशिशें बेकार न जाए और मुख्य न्यायाधीश जो अपनी कार्यकाल में बार-बार न्याय का सिर ऊँचा और जनता में उसका भरोसा बहाल करते रहे हैं, हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि वह इस धर्म संसद और उसमें की गयी ''हेट स्पीच'' और आक्रमतापूर्ण बकवास का सख़्त नोटिस लेंगे और एक बार अल्पसंख्यकों में अपना भरोसा बहाल करेंगे कि स्वतंत्र, लोकतांत्रिक और धर्मनिर्पेक्ष भारत में उनके अधिकार को न कोई बहुसंख्यक रौंद सकती है न कोई शासक उनके अधिकार को तिरछी नज़र से देख सकता है।

बहरहाल आज इन गंभीर हालात में जब हमारे शासक भी साम्प्रदायिक तत्वों के बंदी बन चुके हैं हमारा न्यायिक व्यवस्था ही उम्मीद की एक किरण के तौर पर बाकी रह गया है और शायद इसलिए आज देश का मज़लूम अल्पसंख्यक विशेषकर मुसलमान अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए मुख्य न्यायाधीश रमन्ना की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं।❑❑

शेष.... मुझे किसी ने नहीं बताया था....इ

हैं। वह बात के पक्के इंसान हैं। वह एकता में यकीन रखने वाले इंसान हैं। भारतीय क्रिकेट का जो नक्शा बदला है उसका श्रेय उन्हें अधिक जाता है।

सवाल:- आस्ट्रेलिया के ख़िलाफ 2001 में आपको अहसास हुआ कि भज्जीसे टर्बनेटर बन गए?

जवाब:- वही सीरीज ऐसी थी जिसमें हो सकता था कि मेरा कैरियर खत्म जाता, लेकिन उस सीरीज ने मेरा कैरियर खत्म हो जाता पर उसी सीरीज ने मेरा कैरियर बना दिया। उस सीरीज ने जालंधर के सोनू को हरभजन सिंह बना दिया। उससे पहले लोग मुझे जानते नहीं थे। बस इतना जानते थे कि थोड़ी बहुत ऑफ स्पिन गेंदबाज़ी कर लेता है, छह सात टेस्ट मैच खेला है। आपको अपनी पहचान बनाने के लिए बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाना ही पड़ता है। अगर प्रदर्शन नहीं करोगे तो कोई नहीं पूछेगा।

सवाल:- अभी विश्व कप के समय भी कुछ पाकिस्तानी क्रिकेटरों ने टवीट किया था तो आपने ठीक-ठाक जवाब दिया था..?

जवाब:- दुनिया को बोलती है, क्या नहीं, अब वे पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, उनको लगता है कि वे कुछ बोल रहे हैं तो पहले अपना घर देख लें। आपने खुद क्या किया है क्रिकेट में। और क्या बात कर रहे हो। ग़लत बात जो ना बोलता है और न सुनता है वह हरभजन सिंह है, सच के लिए खड़ा रहता हूं।

सवाल:- आपके पसंदीदा क्रिकेटर कौन रहे हैं?

जवाब:- सचिन तेंदुलकर, मुथैया मुरलीधरन, शेन वार्न, अनिल कुंबले, स्टीव वॉ ये कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो हर दौर में मेरे पसंदीदा खिलाड़ी रहे हैं।❑❑

शेष.... आख़िर उत्तर प्रदेश....

और जिस तरह से प्रियंका गांधी यूपी में सक्रिय हैं उससे साफ है कि विपक्ष के तौर पर कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर रही है। टॉप-2 में कांग्रेस शायद न आ पाए लेकिन क्या वो तीसरे नंबर पर आ सकेगी? और अगर ऐसा होता है तो कौन सी पार्टी टॉप-3 से बाहर होगी? ये देखने वाली बात होगी लेकिन सोशल मीडिया कैंपेन और मीडिया में कांग्रेस अच्छा कर रही है। ये 'अच्छा' बूथ स्तर, वार्ड स्तर और नंबरों में दिख जाए तो पार्टी में जान पड़ जाएगी ये तय है। प्रियंका गांधी के भाषणों से राहुल के भाषणों की तरह मीम्स नहीं निकाले जाते। ये एक नेता के तौर पर प्रियंका के लिए अच्छा है लेकिन प्रियंका को अगर वाक़ई यूपी जीतना है तो उन्हें कुछ सवालों के जवाब बेबाकी और स्पष्टता के साथ देने चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि अगर यूपी में जीत मिली तो वह किसे सीएम बनाएंगी। उन्हें ये भी बताना चाहिए कि क्यों उनकी पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के चेहरे उनके साथ उ.प्र. में नहीं दिखाई दे पा रहे हैं। ऐसे अनेक सवाल है जो यूपी की जनता के मन में है। यह अभी दूर की कौड़ी ही कहा जाएगा कि यूपी की जनता आख़िर क्षणों में किस पार्टी की ओर करवट लेती है, क्योंकि सभी पार्टियों की कमज़ोरियों और गड़बड़ी से जनता वाकिफ़ है, चाहे वह योगी जी हो, या अन्य!❑❑

शेष.... 50 सालों में बांग्लादेश ने....

लिए अलग से जोन नहीं बनाए। उसके बजाय उसने वेयरहाउस सिस्टम का लाभ देश में कहीं के भी गारमेंट एक्सपोर्टर्स को दिया। इसलिए वे अपनी सहूलियत के हिसाब से कहीं भी फेक्ट्री लगा पाए। इससे इन कंपनियों को लागत कम रखने में मदद मिली। आज बांग्लादेश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गारमेंट युवा महिलाओं को रोज़गार मिला हैं कामगारों में महिलाओं की भागीदारी और बढ़ी है। 80 के दशक के मध्य में सरकार नई औद्योगिक नीति लेकर आई। भारत से पांच वर्ष पहले। इस तरह बांग्लादेश में एक झटके में 'लाइसेंस राज' का ख़ात्मा हुआ।

80 के दशक के आख़िर तक व्यापार के क्षेत्र में उदारीकरण हुआ। पहले जहां देश में ज़रूरत की चीज़ें बनाने पर ध्यान था, उस नीति को छोड़ दिया गया। सरकारी कंपनियों का अर्थव्यवस्था में दबदबा था। लेकिन समय के साथ सरकार ने ग्रामीण समुदाय और निजी कंपनियों की उद्यमशीलता को बढ़ावा दिया। सच कहूं तो ये बदलाव आसान नहीं रहे। इन्हें सहज मानना बांग्लादेश के मुश्किल राजनीतिक सफर के साथ नाइंसाफी होगी। हमारा देश क्रूर राजनीतिक हत्याओं का गवाह बना। उसने सैन्य तानाशाह देखी और बग़ावत करके लोकतंत्र हासिल किया। मेरा बांग्लादेश से गहरा और निजी रिश्ता है। मेरी आयु मेरे देश से अधिक है। इस देश के जन्म में मेरे माता-पिता, सास ससुर और मेरे परिवार के कई लोगों की भूमिका रही है। वे पहली पीढ़ी के राष्ट्र निर्माता रहे। उन्होंने हमें एक आज़ाद मुल्क दिया। 50 वर्ष पूरे करने के बाद मन में यही प्रश्न आता है कि बांग्लादेश के आने वाले 50 साल कैसे होंगे? इतना तो यह है कि ये आसान नहीं होंगे, लेकिन इतिहास साक्षी है कि जो भी चुनौतियां जाएंगी, बांग्लादेश उनसे पूरी ताक़त से निपटेगा।

-जुनैद के अहमद

शेष.... 5सेवा करने के लिए....

की विशाल सेना से अकेले ही भीड़ गई थी। न ही महात्मा गांधी जैसे लोग हैं, जिन्होंने सिर्फ दो कपड़ों में अंग्रेज़ी सरकार की नींव तक हिला दी और उनको एक दिन भारत छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा था। इन लोगों को सेवा करने के लिए किसी पद की आवश्यकता नहीं पड़ी, न ही सिक्योरिटी, बंगले और बड़ी-बड़ी गाड़ियों की, लेकिन दुख की बात है कि इन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर हमारे नेता जनता से वोट मांगते हैं और सत्ता मिलने पर खुद 'राजसी' ज़िन्दगी जीते हैं कोई विरला ही इन सब का अपवाद होता है। हम सबको चाहिए कि हम हर पांच वर्ष बाद इनमें से किसी न किसी को हमारी सेवा करने का अवसर देते रहें। ये हमारी समस्याएं 'हल' करते रहें और देश 'तरक्क़ी' की राह पर चलता रहे, इसके अलावा हम लोग और कर भी क्या सकते हैं।❑❑

शेष.... मंज़र पस-मंज़र

माह से कम होने लगे और धीरे-धीरे कोरोना की भयावहता में कमी आने लगी। मगर अब ओमीक्रॉन की दस्तक के बाद दिसंबर माह में फिर वही स्थिति है। लोगों ने मास्क को तिलांजलि देना शुरू कर दिया है। इस आदत को बदलने की सख़्त ज़रूरत है।

ओमीक्रॉन के पूरे देश में लगातार बढ़ रहे केसों को देखते हुए हमें ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। वैज्ञानिकों को इस बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल नहीं हो पा रही वे इसकी तीव्रता व एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होने वाली संवाहन क्षमता का चिकित्सीय विश्लेषण व अध्ययन कर रहे हैं अत: इस अंतराल अवधि में मास्क लगाकर हम किसी भी संभावित विभिषिका को यदि टाल नहीं सकते तो न्यूनतम बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। मगर यह कार्य राज्य स्तर से ही इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे देश के प्रत्येक जिले में ग्रामीण स्तर तक यह संदेश जाये कि मास्क कोरोना के ख़िलाफ़ एक 'सामाजिक दवाई' है। इसे इस तथ्य की रोशनी में देखा जाना चाहिए कि अभी तक ओमीक्रो के ख़िलाफ़ वैक्सीन की प्रतिरोधी क्षमता की जांच की जा रही है अत: उन लोगों को भी सावधानी बरतनी की आवश्यकता होगी जिन्होंने कोरोना रोधी वैक्सीन के दोनों डोज ले लिए हैं। इसके साथ हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि यूरोपीय देशों में कोरोना संक्रमण के मामले फिर से बढ़ने की ख़बरें आ रही हैं और विश्व स्वासयि संगठन के अनुसार विश्व के 60 से ज़्यादा देशों में यह पहुंच चुका है। हालांकि संसद में गृह मंत्रालय की संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए हिदायत दी थी कि सरकार को कोरोना उत्सर्जन के विभिन्न संक्रमणों के मद्देनज़र 'बूस्टर डोज' लगाए जाने के बारे में सोचना चाहिए और देश के प्रत्येक व्यस्क नागरिक को कोरोना के दो टीके लगाये जाने की प्रक्रिया को पूरा करना चाहिए। इसके लिए घर घर जाकर टीका लाये जाने की पद्धति अपनाई जानी चाहिए। राज्यसभा के कांग्रेस सांसद श्री आनंद शर्मा की अध्यक्षता में गठित इस समिति ने सिफारिश की कि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए और इसकी लपेट में गैर टीकाकृत जनसंख्या विशेषकर बच्चों के आने की कथित संभावनाओं को देखते हुए प्रत्येक राज्य में कोरोना से मुक़ाबला करने का स्वास्थ्य ढांचा मज़बूती के साथ खड़ा रहना चाहिए। अत: किसी भी आशंका का मुक़ाबला करने का प्राथमिक उपाय मास्क लगाना और सामाजिक दूरी बनाए रखना होना चाहिए।❑❑

SHANTI MISSION (HINDI WEEKLY) NEW DELHI Postal Registration No. DL(C)-01/1266/2021-23
Publishing Date : **02 Jan.2022** Posting Days : **MON. - TUE.** at **N.D.P.S.O.** New Delhi-110002 R.N.I. 57270/93

आधार कार्ड और चुनाव सुधार

मास्क लगाना 'सामाजिक दवाई'

आधार कार्ड और चुनाव सुधार

केन्द्रीय मंत्रीमंडल ने चुनाव आयोग की सिफारिशों के आधार पर मतदाता कार्डों स्वैच्छिक रूप से आधार कार्ड से जोड़ने पर सहमति दे दी है। इसके साथ ही 18 वर्ष पूर्ण करने वाले युवाओं को भी पांच साल में चार बार अपना दाम मतदाता सूचि में दर्ज कराने की छूट होगी। इसके साथ ही सेना में काम करने वाली महिला फौजियों के पतियों को भी उनके नाम पर वोट डालने की अनुमति प्रदान की जायेगी। इसके लिए सरकार जनप्रतिनिधि अधि नियम-1951 व आधारकार्ड अधिनियम 2016 में संशोधन करेगी। आधार कार्ड से मतदाता कार्ड को जोड़े जाने से दोहरे मतदान की समस्या को समाप्त करने में सफलता मिलेगी और मतदाता सूचि अधिक पारदर्शी होगी। परंतु हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि आधार कार्ड किसी भी व्यक्ति के केवल निवास का प्रमाण पत्र होता है, उसकी राष्ट्रीयता का नहीं। इसका उपयोग सरकारों द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं को लाभ प्रदान करने के लिए मुख्य रूप से किया जाता है। इसके बावजूद चुनाव आयोग ने यदि इस आशय का सुझाव दिया है तो उसने इस सम्बन्ध में समुचित मेहनत की होगी। इन बदलावों को चुनाव सुधार कहना ज़्यादा प्रासंगिक इसलिए नहीं है क्योंकि इससे भारत की चुनाव प्रणाली की मुख्य ख़ामियों का विशेष लेना देना नहीं है। यह जगज़ाहिर हक़ीक़त है कि भारत में चुनाव लगातार इस क़दर महंगे होते जा रहे हैं कि कोई साधारण सुविज्ञ नागरिक इनमें खड़े होने की हिम्मत भी नहीं जुटा सकता। चुनावों पर धन का प्रभाव इतना बढ़ चुका है कि भारत का प्रजातंत्र कभी-कभी धनतंत्र का दास लगने लगता है। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए यह स्थिति किसी भी सूरत में अच्छी नहीं कही जा सकती। इसका तोड़ ढूंढने के लिए अभी तक देश में कई बार चुनाव सुधार समितियों या आयोगों गठन भी हो चुका है मगर नतीजा ठांक के तीन पात की तरह ही रहा है। इसकी मुख्य वजह राजनीतिक पार्टियां हैं जो यथास्थिति में बदलाव नहीं चाहती हैं। चालू व्यवस्था में इनके हित इस तरह गुंथ चुके हैं कि चुनाव सुधारों का नाम लेते ही इनके पसीने छूटने लगते हैं जबकि लोकतंत्र में स्वतंत्र व निर्भीक व बिना लालच के मताधिकार का प्रयोग होना जनता की सरकार बनने की पहली शर्त होती है। बेशक, संविध ान में यह उल्लिखित है कि कोई भी चेतन वैध नागरिक किसी भी चुनाव में खड़ा हो सकता है मगर व्यावहारिक रूप में हम जो देखते हैं कि केवल बड़े-बड़े धनाढ्य लोग ही इस दम पर विभिन्न पार्टियों से टिकट पाने में सफलता प्राप्त कर लेते हैं उनकी निजी वित्तीय हालत मज़बूत होती है।

चुनावों में अपराधी छवि के लोगों के प्रवेश को क़ानूनी प्रावधान करके रोकने के भी विभिन्न उपाय किये गये हैं और वे कुछ मायनों में भी कारगर भी रहे हैं मगर धन से छुटकारा दिलाने का अभी कोई उपाय नहीं किया गया है। आश्चर्य नहीं किया जाना चाहिए कि स्व॰ इंदिरा गांधी की सत्ता के ख़िलाफ़ 1974 में शुरू किया जय प्रकाश नारायण का आंदोलन चुनाव सुध ारों के पक्ष में भी था।

चुनावों में अपराधी छवि के लोगों के प्रवेश को क़ानूनी प्रावधान करके रोकने के भी विभिन्न उपाय किये गये हैं और वे कुछ मायनों में भी कारगर भी रहे हैं मगर धन से छुटकारा दिलाने का अभी कोई उपाय नहीं किया गया है। आश्चर्य नहीं किया जाना चाहिए कि स्व॰ इंदिरा गांधी की सत्ता के ख़िलाफ़ 1974 में शुरू किया जय प्रकाश नारायण का आंदोलन चुनाव सुधारों के पक्ष में भी था और जिस सम्पूर्ण क्रांति का नाम देकर यह आंदोलन चलाया गया था उसमें चुनावों के अधिक खर्चीला हो जाने का भी एक प्रमुख मुद्दा था। इस घटना को अब 45 वर्ष गुज़र चुके हैं और हम जहां के सतहों पर ही खड़े हुए हैं जय प्रकाश नारायण ने उस समय बम्बई उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री. वी.एम. तारकुंडे के नेतृत्व में एक चुनाव सुधार समिति भी बनाई थी मगर इस आंदोलन की समाप्ति और आपातकाल लग जाने के बाद के हुए चुनावों में 1977 में जब मोरारजी देसाई के नेतृत्व में सरकार गठित हुई तो सबसे पहले उसने तारकुंडे समिति की रिपोर्ट को ही परे करते हुए तत्कालीन अवकाश प्राप्त मुख्य चुनाव आयुक्त पी.एल. शकधर के नेतृत्व में एक चुनाव आयोग गठित कर दिया और इसकी रिपोर्ट को भी बाद में अलमारी में बन्द कर दिया गया। तारकुंडे समिति ने सरकारी ख़र्च से चुनाव कराने का पूरा खाक़ा रखा था। बाद में और भी कई चुनाव सुध ार समितियां बनी जिसमें गोस्वामी समिति का उल्लेख किया जाना आवश्यक है क्योंकि इसकी रिपोर्ट में कुछ मूल सुधार करने की सिफारिश थी। इसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त बने टी॰ एन॰ शेषन ने कोरी वाहवाही बटोरने के लिए चुनाव प्रणाली के स्थान पर चुनाव प्रबंधन में ऐसे संशोध न किये कि उनसे लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व या जश्न कहे जाने वाले चुनाव किसी तेरहवीं के मातम की तरह बदलने लगे। उन्होंने चुनाव प्रबंध न में आम आदमी की शिरकत को न्यूनतम कर दिया। आशय किसी भी रूप में स्व. शेषन की नीयत पर प्रश्न खड़ा करने का नहीं है बल्कि यह है कि उन्होंने भी बुराई की जड़ पर हाथ डालने का कोई प्रयास नहीं किया। चुनाव प्राली में संशोधन की जरूरी पिछले चालीस वर्ष में पनपी विभिन्न मज़बूत क्षेत्रीय पार्टियों को किसी भी सूरत में रास नहीं आती है क्योंकि इन दलों का ढांचा पूरी तरह किसी ख़ानदानी या क़दीमी परचून की दूकान की तरह होता है जिनमें बाप का गद्दी पर बेटा या बेटी संभालते रहते हैं। प्रत्याशियों का चयन करने का मापदंड ये नेता स्वयं तय करते हैं और कहीं-कहीं तो प्रत्याशी बनने की शर्त पहले ही नेता की मुट्ठी गर्म करने तक की होती है। इसीलिए इस समस्या का सिरा राजनीतिक दलों के तंत्र से जुड़ा हुआ है। ज़रूरत इस बात की है हम व्यापक आधारभूत चुनाव सुधारों के बारे में सोचें।

मास्क लगाना 'सामाजिक दवाई'

भारत ने अब तक 131 करोड़ से अधिक लोगों को कोरोना संक्रमण का टीका लगाकर सिद्ध कर दिया है कि इसका आधारभूत स्वास्थ्य ढांचा ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्रों में इस तरह मज़बत है कि राजनीतिक इच्छाशक्ति के चलते इसे न केवल कारगर बनाया जा सकता है बल्कि जन कल्याण की नीति में तब्दील किया जा सकता है। भारत में टीकाकरण को लेकर जिस तरह कोरोना संक्रमण के दूसरे हमले के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में कटु आलोचनाएं हो रही थीं और टीकों की कमी की आशंका व्यक्त की जा रही थी उसे परे धकेलते हुए केन्द्र सरकार ने जो टीका नीति बनाई उसी का यह सफल परिणाम कहा जा सकता है हालांकि ऐसा सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद ही हुआ था जब उसने पूरे देश के लिए एक समान टीका नीति बनाने की हिदायत दी थी परंतु संसद में स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना संक्रमण के अगले स्वरूप 'ओमीक्रॉन' ख़तरे से भी देशवासियों को जिस तरह आगाह किया उससे स्पष्ट होता है कि किसी भी नागरिक को इस बारे में लापरवाह होने की आवश्यकता नहीं है। सावधानी के तौर पर फिलहाल 'बूस्टर डोज' की आवश्यकता को स्वास्थ्य मंत्री ने नकार दिया और कहा कि इस बारे में देश के वैज्ञानिकों पर भरोसा रखना चाहिए और उनकी सलाह के अनुरूप ही अगले क़दम उठाये जाने चाहिए।

भारतीय वैज्ञानिक ओमीक्रॉन को लेकर गहन चिकित्सीय जांच परख व अध्ययन कर रहे हैं। मगर देश में बने कोरोना कार्यदल के प्रमुख डॉ॰ एन॰ के॰ पाल का कहना है कि ओमीक्रान संक्रमण के उत्सर्जन की घटनाओं को देखते हुए बहुत ज़रूरी है कि देशवासी मास्क लगाने पर कोई कोताही न बरतें और इसे अपनी सामान्य जीवनशैली का अंग बनाये क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर आने से पहले पिछले मई माह से पहले लोगों ने मास्क लगाने पर ढिलाई बरतनी शुरू कर दी थी। यही स्थिति फिलहाल बनी हुई है।

आम लोग मास्क को लेकर लापरवाह हो रहे हैं जो किसी भी तरह उचित नहीं है। मुसीबत सिर पर पड़ जाने पर ही मास्क लगाने से पहले ही हमें इसे अपनी जीवनशैली में शामिल कर लेना चाहिए क्योंकि डॉ. पाल के अनुसार मास्क ऐसी सामाजिक वैक्सीन या टीका है जो किसी भी संक्रमण के लिए प्रतिरोधी औज़ार का काम करती है। इसं संक्रमण से डर कर नहीं बल्कि सामान्य परिस्थितियों में ही अपनाना बेहतर रणनीति होती है जिससे कोरोना के किसी भी उत्सर्जन (वेरिएंट) की तीव्रता को कम किया जा सके। यह हक़ीक़त है और इसमें किसी प्रकार की शंका के लिए कोई जगह इसलिए नहीं है क्योंकि विगत मई माह में जब कोरोना की दूसरी लहर चलने पर आम आदमी ने मास्क लगाना शुरू किया तो संक्रमण के मामले अगस्त

देश में बने कोरोना कार्यदल के प्रमुख डॉ॰ एन॰ के॰ पाल का कहना है कि ओमीक्रान संक्रमण के उत्सर्जन की घटनाओं को देखते हुए बहुत ज़रूरी है कि देशवासी मास्क लगाने पर कोई कोताही न बरतें और इसे अपनी सामान्य जीवनशैली का अंग बनाये क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर आने से पहले पिछले मई माह से पहले लोगों ने मास्क लगाने पर ढिलाई बरतनी शुरू कर दी थी।

बाक़ी पेज 11 पर

ज़रूरी ऐलान

आपकी ख़रीदारी अवधि पते की चिट पर अंकित है। अवधि की समाप्ति से पूर्व रक़म भेजने की कृपा करें।

रक़म भेजने के तरीक़े:-

❶ मनीआर्डर द्वारा ❷ Paytm या PhonePe द्वारा **9811198820** पर
SHANTI MISSION
❸ ऑनलाइन हेतु बैंक खाते का विवरण
SBI A/c **10310541455**
Branch: **Indraprastha Estate**
IFS Code: **SBIN0001187**

ख़रीदारी चन्दा

वार्षिक	Rs.130/-
6 महीने के लिए	Rs.70/-
एक प्रति	Rs.3/-

जानकारी के लिये सम्पर्क करें
साप्ताहिक
शांति मिशन
1, बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग,
नई दिल्ली-110002
फोन : 011-23311455

अपने प्रिय अख़बार साप्ताहिक शांति मिशन को इंटरनेट पर देखने के लिये लॉगऑन करें:
www.aljamiat.in ——— www.jahazimedia.com
Mob. 9811198820 — E-mail: Shantimissionweekly@gmail.com

जमीअत ट्रस्ट सोसायटी की तरफ से मुद्रक, प्रकाशक शकील अहमद सैयद ने शेरवानी आर्ट प्रिंटर्स, 1480, क़ासिमजान स्ट्रीट, बल्लीमारान, दिल्ली-6 से छपवाकर मदनी हाल, न. 1, बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित किया। संपादक:- मोहम्मद सालिम, फोन:- 23311455, 23317729, फैक्स:- 23316173